04 - सनातन धर्म की गौरव प्रतिष्ठा का प्रतीक आयोजन...

05 - यूं शुरू हुआ था विक्रम महोत्सव, विक्रम भारत का...

A Daily News Magazine

भोपाल

शुक्रवार, 28 फरवरी, 2025

06 - शासन के आदेश की अवहेलना कर शिक्षिका को किया...

07 - जनजातियों का चल रहा स्वर्णिम युगः राज्यपाल

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 172, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

विदा के वक्त इक वादा
किया था वापसी का भी
कहां आसान होता है
किसी का लौटना
इस बात से अंजान
थी उस वक्त
मुझे लगता था
बस दो चार दिन की
बात ही तो है
मैं जिस रस्ते से होकर जा रही हूं
बस इसी रस्ते से वापस लौट आऊंगी
मगर ये क्या
हज़ारों रास्ते थे मुंतजिर
पलकें बिछाए यूं
कि इन रस्तों के जालों में
उलझकर रह गई हूं मैं
वो इक वादा
हर इक दीवार पर
चस्पा है विज्ञापन की सूरत में
जिसे हम आते जाते देखते तो हैं
मगर बस देखते भर हैं।

– संजू शब्दिता

प्रसंगवश

बिहार में पुराने चेहरे-पैंतरे से कितनी चल पाएगी राजनीति?

अरविंद मोहन

आ खिरकार निशांत कुमार का बयान भी आ गया कि एनडीए को चाहिए कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने की घोषणा कर दे। निशांत माने नीतीश कुमार के पुत्र। पहली बार सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान देकर उन्होंने कई तरह के संकेत दिए। निश्चित रूप से पहला संकेत तो राजनीति में आने का है। बीते बीस साल से मुख्यमंत्री के संग रहने और अकेली संतान होने के चलते सारा लाड़-प्यार पाने के बावजूद अभी तक उनके किसी आचारण को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं थी। बल्कि वे इतने शांत और सावधान तरीके से रहते थे कि काफ़ी सारे राजनैतिक पंडित उनके सामान्य होने पर ही शक करते थे। अब अगर वे बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद और पचास साल की उम्र में पार्टी तथा समाज के अनेक पक्षों से बार बार की जा रही मांग के बाद सक्रिय होने का फैसला करते हैं तो उन्हें शुभकामना दी जा सकती है। अपनी स्वर्गवासी मां के जन्मदिन पर आयोजित किसी कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही और जदयू का प्रदर्शन पहले से बेहतर होने की बात भी कही।

और यह संयोग है कि उनका कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने बिहार दौरे में नीतीश जी को 'लाड़ला मुख्यमंत्री' बताने के दो दिन बाद ही हुआ। प्रधानमंत्री ने इस दौरे के साथ ही भाजपा और एनडीए के चुनाव अभियान का शंखनाद भी कर दिया। इसमें लोगों को पाँच साल पहले करोना महामारी के बीच में ही हजारों रंगीन टीवी सेट के माध्यम से बिहार में ऑनलाइन शंखनाद करने वाला प्रसंग भी याद आया क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक साथ बिहार के सारे कोनों को छू लिया था। उन्होंने नीतीशजी को आगे रखकर चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की। शायद उनके पास ऐसा कोई और नाम है भी नहीं। लेकिन बीते साल भर में एनडीए और भाजपा की तरफ से यह कहा जाता रहा है। कमाल यह है कि इसके बावजूद निशांत कुमार को यह बात दोहराने की ज़रूरत हुई। बीते दो तीन महीनों में विपक्षी राजद की तरफ से नीतीश कुमार के एक बार फिर से पाला बदलने की बात उछाली जा रही है और लालू प्रसाद यादव ने अब नीतीश का स्वागत करने की बात भी चला दी है।

खुद नीतीश कुमार भी इस सवाल पर अपने की आचरणों से संदेह गहरा रहे हैं। दिल्ली के अपने दो दौरों में उन्होंने बीजेपी के किसी नेता से भेंट नहीं की या बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें समय न दिया। वे दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में भी नहीं गए, जबकि एनडीए के बाकी सभी मुख्यमंत्री थे। पर उससे भी ज़्यादा चर्चा उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं का दिल्ली आकर पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंगना है और इसे राजनैतिक पंडित नीतीश कुमार की घेराबंदी बताते हैं।

नीतीश बिहार में भी बीजेपी के एक गुट के व्यवहार को लेकर बहुत प्रसन्न नहीं रहते। यह समूह बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की वकालत भी करता है। यह अटकल भी लगती है कि चुनाव तक बीजेपी उनको आगे रखकर बाद में कोई और पद या ज़िम्मा दे देगी। नीतीश और उनके समर्थक यह नहीं चाहते।

अब जाने अनजाने बीजेपी का समर्थन आधार बढ़ता गया है लेकिन अगड़ों को छोड़कर कोई और सामाजिक समूह पक्का समर्थक नहीं है-बीच के प्रयास नीतीश मामले में हां-ना के चक्कर में खिसक गया है। इसलिए निशांत के बयान का एक तीसरा मतलब बीजेपी के संग अपनी पार्टी के अगड़े नेताओं के लिए भी है जिनकी बीजेपी से नज़दीकी जगजाहिर है। यही लोग नीतीश कुमार के पाला बदलकर बीजेपी के संग आने का माध्यम भी बने थे और अभी दिल्ली में जमे हैं। बीजेपी को भी इस बयान का मतलब यह निकालना चाहिए कि नीतीश कुमार ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा जैसों के समानांतर किसी अपने और ज़्यादा भरोसेमंद को खड़ा करना चाहते हैं। निशांत पिता की इच्छा देखकर ही पंख फैलाना शुरू कर रहे हैं। इस क्रम में आईएएस रामचन्द्र प्रसाद सिंह का प्रसंग याद करना चाहिए जो ज़्यादा पंख फैलाकर झुलस चुके हैं। पर जब वे नीतीशजी के साथ थे तो बिना राजनैतिक पृष्ठभूमि के भी सबसे भरोसेमंद थे।

दूसरी ओर कांग्रेस और राजद के रिश्ते एनडीए के घटकों से भी ज़्यादा ख़राब हैं। हरियाणा का चुनाव हारने के बाद तो अखिलेश और तेजस्वी का रुख भी बदला है। दिल्ली चुनाव ने दूरी और बढ़ाई और अब तो एक-दूसरे के खिलाफ़ बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी कुछ लोग अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस का भी आधार या स्वीकृति बढ़ी है, लेकिन कोई एक या दो ठोस सामाजिक आधार नहीं हैं। मुसलमान समर्थक हैं लेकिन राजद साथ न हो तो उनका वोट मिलने का भरोसा नहीं है। संगठन कमजोर है और अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे उत्साही उसके पास हैं तो लालू-तेजस्वी उनको ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं। लालू जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में अहीरों को कम टिकट दिए, कोइरी समाज को ज़्यादा टिकट दिए और वाम दलों समेत सारे विरोधियों को साथ लेकर अच्छी टक्कर दी लेकिन पहले दो राउंड के बाद बीजेपी ने फिर से जंगल राज का शोर मचाकर बाजी पलट दी।

इस बार यह शोर पहले से मच रहा है। दूसरी ओर बीजेपी सरकार ने लालू जी और उनके परिवार पर क़ानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो चुनाव पास आने तक नाटकीय रूप ले लेगा। लालू जी इससे निजी रूप से कमजोर पड़ें न पड़ें, राजनैतिक रूप से कमजोर होंगे। उधर राजद का मतलब अहीर और मुसलमान गठजोड़ से आगे बढ़ ही नहीं रहा है और ऐसा गठजोड़ जैसे ही ताक़तवर दिखता है बीजेपी को सुविधा हो जाती है और ग़ैर यादव पिछड़ों का वोट बढ़ जाता है तथा अगड़ों का वोट ज़्यादा गोलबंद होकर मिलता है। जब तक नेतृत्व में हिस्सेदारी और लोकतांत्रिक व्यवहार की उम्मीद न हों दूसरे पास आते नहीं और लालू जी से परिवार से अलग नेता और लोकतान्त्रिक आचारण की उम्मीद करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल लक्ष्य है। दुर्भाग्य यह है कि जिस बिहार को अब नई राजनीति की ज़रूरत है वहाँ सब कुछ दो थके पुराने चेहरों के इर्द-गिर्द चलता दिखता है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

ना कोई सूचना और ना निमंत्रण, फिर भी पहुंचे करोड़ों श्रद्धालु

● महाकुंभ पर पीएम मोदी बोले-कोई कमी रही हो तो माफ करना ● मेले के समापन पर पीएम मोदी ने बताया यह एकता का महाकुंभ

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रयागराज में 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन भव्य तरीके से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक आयोजन को एकता का महाकुंभ बताया और अपने ब्लॉग में लिखा कि बिना किसी औपचारिक निमंत्रण या सूचना के करोड़ों श्रद्धालु इस आयोजन में पहुंचे, जिससे भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का अनुपम दृश्य देखने को मिला। पीएम मोदी ने लिखा कि इस महाकुंभ में देशभर से श्रद्धालु जुटे, जिनमें संत, महात्मा, बाल-वृद्ध, महिलाएं और युवा सभी शामिल थे। उन्होंने इसे भारत की एकता और समरसता का प्रतीक बताया और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान 'देवभक्ति से देशभक्ति' का जो संकल्प लिया गया था, उसे इस महाकुंभ में मूर्त रूप मिला। पीएम मोदी

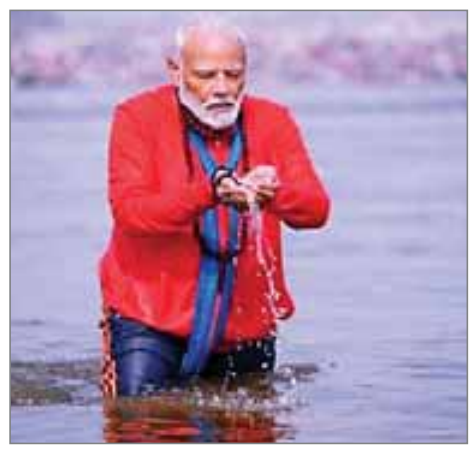

ने इस आयोजन की भव्यता पर चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां बिना औपचारिक निमंत्रण के इतनी विशाल संख्या में लोग पहुंचे हों। उन्होंने प्रशासन, सफाईकर्मियों, पुलिसकर्मियों, नाविकों और प्रयागराज के स्थानीय निवासियों की सेवा भावना की भी प्रशंसा की, जिन्होंने महाकुंभ के दौरान आने वाले करोड़ों लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा। अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने लिखा कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाला एक महायज्ञ था। उन्होंने इसे एक नए भारत की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि इस आयोजन ने भारत के उज्ज्वल भविष्य की एक झलक पेश की है, जहां आध्यात्मिकता और विकास एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।

संगम में डुबकी लगाकर लोग धन्य हो गएः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने लिखा, 'प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन, आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए, नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर, त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को ना औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किस समय पहुंचना है, उसकी कोई पूर्व सूचना थी।

प्रयागराज पहुंचे योगी, स्वच्छता कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों को दिया बड़ा तोहफा

सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ा, अब 16 हजार रुपए मासिक मिलेंगे

महाकुंभ में शामिल सफाई ,स्वास्थ्य कर्मियों को स्वच्छ कुंभ कोष से मिलेगा बीमा

प्रयागराज (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला 2025 के समापन के मौके पर सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सफाई कर्मचारियों के सम्मान समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा। 1 अप्रैल से हर सफाई कर्मचारी को 16,000 रुपये महीना वेतन मिलेगा। साथ ही, सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों को 5,00,000 रुपये की स्वास्थ्य बीमा का भी ऐलान किया। वर्तमान समय में यूपी में संविदा पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को 14 हजार रुपये मासिक सैलरी मिलती है। इस प्रकार इसमें दो हजार रुपये का इजाफा सरकार की ओर से किया गया है। संगम तट पर इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा की आरती की। इसके बाद विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया। महाकुंभ मेले के दौरान सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने वाले स्वच्छता कर्मियों और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले मेडिकल कर्मचारियों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि हर किसी के सहयोग से यह महाकुंभ मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रयागराज महाकुंभ में काम कर रहे स्वच्छताकर्मियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सफाईकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों को उपहार के साथ ही स्वच्छ कुंभ कोष से बीमा प्रमाण पत्र प्रदान किया।

साथ ही, मंच से ऐलान किया कि जो भी स्वच्छताकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी महाकुंभ के महाआयोजन में सहभागी बने, उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त बोनस के रूप में 10 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। सीएम योगी ने यह भी ऐलान किया कि अप्रैल से प्रदेश सरकार एक कॉर्पोरेशन का गठन करने जा रही है। इसके माध्यम से हर स्वच्छताकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और उन सभी कर्मियों को जिन्हें मिनिमम वेज नहीं मिल पाता था, उन्हें सरकार 16 हजार प्रतिमाह प्रदान करेगी।

चित्रकूट में शाह ने 'नवीनीकृत प्रकल्प राम दर्शन' का रिमोट से लोकार्पण किया

जनता कई नेताओं को राजनीति छुड़वा देती है : गृहमंत्री शाह

सतना (नप्र)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार चित्रकूट में कहा, राजनीति के क्षेत्र में जनता कई नेताओं को राजनीति छुड़वाती है। नानाजी ने केवल 60 वर्ष की आयु में जब जनता पार्टी अधिकार में थी तब निर्णय किया कि 60 के हो गए बाकी का जीवन एकात्म मानववाद को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। इसके बाद एकात्म मानववाद और अंत्योदय का सिद्धांत दिया। इसके लिए चित्रकूट को चुना। नानाजी की 15वीं पुण्यतिथि पर अमित शाह ने उनको श्रद्धांजलि दी, दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण और रामदर्शन परिसर का लोकार्पण किया। शाह ने कहा, कुछ लोगों के जीवन ऐसे होते हैं, जो कुछ वर्षों नहीं, युगों तक अपना असर छोड़ते हैं और युग को परिवर्तनकारी बनाने का काम करते हैं। नानाजी उनमें से एक हैं। नानाजी ने जीवन का क्षण-क्षण और शरीर का कण-कण भारत माता को समर्पित किया। वे शतायु हुए राजनीति में अजातशत्रु जीवन जीकर दुनिया छोड़कर जाना बड़ी बात है। मैंने किसी को नानाजी के बारे में कभी किसी को गलत बात करते नहीं सुना। चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष को हो। राजनीति में रहते हुए सर्व स्वीकृति लाना भी कठिन है। इतने लंबे जीवन में नानाजी का विरोध करने का साहस किसी ने नहीं किया।

नानाजी ने राजनीति में अनेक सिद्धांत स्थापित किए

पश्चिम से उठाए गए सिद्धांतों का हिंदीकरण करके नीतियां बनाने का संतोष जवाहर लाल नेहरू की कांग्रेस की सरकार ने किया। उस वक्त पंडित दीनदयाल ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तावित करके बताया हमारा हमारी विदेश नीति कैसी हो, विश्व को देखने का नजरिया कैसा हो वो किया। भारत के विकास के मॉडल को अंत्योदय के रूप में रखा। एक ही कालखंड में दो महापुरुष भारतीय राजनीति ने देश को दिए। दोनों का जन्म 1916 में हुआ। नानाजी देशमुख और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जब देश आजाद हुआ, नीतियां बन रही थीं, जो भारत का सम्मान करते हैं वो सभी लोग आजाद हुए देश की नीतियों को बड़े दुख और चिंता के साथ देख रहे थे क्योंकि, देश की विदेश नीति हो, अर्थ नीति हो, शिक्षा नीति, कृषि नीति हो एक में भी हमारे चिर पुरातन राष्ट्र की मिट्टी की खुशबू नहीं थी।

विक्रमोत्सव 2025

उज्जयिनी की आध्यात्मिक और ज्ञान परंपरा के वैभव का प्रदर्शन

उज्जैन। उज्जैन में विक्रम उत्सव का शुभारंभ बुधवार की सुबह कलश यात्रा से हुआ। दशहरा मैदान पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाशिवरात्रि पर 125 दिवसीय विक्रम महोत्सव एवं विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि उज्जैन के आदर्श नायक सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशा अनुरूप ही गुरुवार की शाम विक्रमादित्य शोधपीठ में उज्जयिनी के ऐतिहासिक प्रतीकों की प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का अवलोकन पद्मश्री भगवतीलाल राजपुरोहित, पूर्व कुलपति प्रो राम राजेश मिश्रा, पूर्व कुलपति प्रो बालकृष्ण शर्मा , पुरातत्व विद् डॉ रमन सोलंकी, विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी, समीक्षक डॉ जफर महमूद ने किया।

प्रदर्शनी को निहारने के बाद विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो अर्पण भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा कि भारत की गौरव गाथा सुनाते चित्रों से साक्षात्कार हुआ। यह अद्भुत अनुभव है। युवा पीढ़ी के लिए इसकी उपादेयता अनंत है। विक्रमादित्य शोध पीठ को साधुवाद। आर्ष भारत शीर्षक प्रदर्शनी में भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा, विक्रम कालीन मुद्रा एवं मुद्रांक, श्री कृष्णा की 64 कलाएं, मालवा की चित्रवण शैली में, श्री कृष्ण होली पर्व, उज्जैन के 84 महादेव, जनजाति प्रतिरूप, सम्राट विक्रमादित्य और राजकुमारी अयोध्या, पारंपरिक

उज्जैन से डॉ. जफर महमूद

भारतीय वाद्य यंत्र, देवी के 108 स्वरूप, आदि बिंब, देवी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित स्थापत्य कला का प्रदर्शन अनूठे रंग बिखेर रहा है।

अध्यात्मिक गायन वादन

कार्यक्रम में प्रख्यात गायक हंसराज रघुवंशी ने शिव भजनों से समा बांध दिया। पद्मश्री आनंद शिवानी ने विभिन्न वाद यंत्रों से कर्णप्रिय प्रस्तुति दी। उन्होंने ड्रम, प्लास्टिक की बाल्टी ,लोटा, गिलास ,सूटकेस को बजाकर अनूठी कला का प्रदर्शन किया।

इससे पूर्व बुधवार को उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिंबॉब्वे के उद्योग एवं कॉमर्स उप मंत्री श्री एमके मोदी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारे भारत की धरती वीरों महावीरों की धरती है। उज्जयिनी का हमेशा भारत के नायकों से पुराना नाता रहा है। सम्राट विक्रमादित्य आदर्श व्यवस्था के पर्याय हैं। जब-जब सुशासन, धर्म ,न्याय और कर्म की बात होती है, सम्राट विक्रमादित्य को याद किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के सभी प्रमुख 51 महाशिवरात्रि मेला समारंभ एवं सिंहस्थ 2028 की रूपरेखा का लोकार्पण भी किया।

कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, सभापति कलावती यादव, संजय अग्रवाल, राजेश कुशवाहा राजेंद्र भारती एवं मुख्यमंत्री के संस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी उपस्थित थे।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 22 °c | न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार,28 फरवरी 2025

> जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
>
> चाणक्य नीति

तमिल न बोल पाने के लिए जनता से माफी मांगता हूं

अमित शाह बोले-यह दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है

कोयंबटूर (एजेंसी)। तमिलनाडु में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी पर जारी विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया है। शाह बुधवार को कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन में आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में शामिल हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा– सबसे पहले, मैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल न बोल पाने के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मैं महाशिवरात्रि के अवसर

पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे सद्गुरु के निमंत्रण पर यहां आने का अवसर मिला। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर साउथ के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से विवाद बना रहा है। 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद विवाद और बढ़ गया। नई शिक्षा नीति के तहत हर राज्य के छात्रों को तीन भाषा सीखनी होगी, जिनमें से एक हिंदी होगी। तमिलनाडु में इसको लेकर काफी विरोध हो रहा है। राज्य में मौजूदा सरकार के कार्यकर्ता जगह–जगह हिंदी लिखे नामों पर कालिख पोत रहे हैं। सीएम एमके स्टालिन ने मंगलवार को कहा था कि केंद्र हमारे ऊपर हिंदी न थोपे। अगर जरूरत पड़ी तो विरोध करेंगे।

वक्फ बिल में 14 बदलावों को केंद्र की मंजूरी

10 मार्च से होने वाले संसद सत्र में लाना संभव

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार

किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था। 27 जनवरी को वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही जेपीसी ने ड्रॉफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। भाजपा की अगुआई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। अगस्त 2024 में वक्फ बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था।

अब राज्य नहीं बांट पाएंगे चुनावी रेवड़ियां ! जल्द कसेगी नकेल

सेंट्रल टैक्स में राज्यों का हिस्सा काटने की तैयारी में केंद्र सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी में कटौती कर सकती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार वित्त आयोग को इसकी सिफारिश करेगी। वित्त आयोग टैक्स शेयरिंग और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में सिफारिश करता है। अरविंद पनगढ़िया की अगुवाई वाला यह आयोग 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देगा जिसे 2026-27 में लागू किया जाएगा। आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। एक सूत्र ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 फीसदी से घटाकर 40 फीसदी करने की सिफारिश कर सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट मार्च के अंत तक इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।

उसके बाद इसे वित्त आयोग के पास भेजा जाएगा। टैक्स रेवेन्यू में 1 फीसदी की कटौती से राज्यों को करीब 35,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यह आंकड़ा इस साल के अनुमानित टैक्स कलेक्शन पर आधारित है। इस बारे में वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग ने ईमेल का जवाब नहीं दिया। सूत्रों ने कहा कि 1980 में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 20 फीसदी था जो अब 41 फीसदी है। लेकिन आर्थिक सुस्ती के कारण केंद्र का खर्च बढ़ गया है। यही वजह है कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कम करने की मांग की जा रही है। 2024-25 में केंद्र का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8 फीसदी रहने का अनुमान है जबकि राज्यों के मामले में यह 3.2 फीसदी है।

भाजपा फर्जी वोटरों की मदद से दिल्ली में जीती: ममता

- भतीजे अभिषेक ने बीजेपी में जाने से कर दिया इनकार

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में कहा, भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव फर्जी वोट के जरिए जीता। इसमें चुनाव आयोग ने मदद की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ईसी की मदद से फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल किया। ममता ने यह

बात पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वोटर लिस्ट सही करने और फर्जी वोटर हटाने को लेकर ईसी ऑफिस के सामने धरना दूंगी। उन्होंने कहा- अगर मैं 26 दिन की भूख हड़ताल कर सकती हूं, तो ईसी के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर सकती हूं। दरअसल, वे 2006 में भूमि अधिग्रहण के विरोध में की गई 26 दिन भूख हड़ताल का हवाला दे रही थीं। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उनके भाजपा में शामिल होने की खबरों को अफवाह बताया।

'आप' विधायकों को विस में जाने से रोका

आतिशी का प्रदर्शन, प्रवेश वर्मा बोले-शीशमहल की जांच होगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन एएपी विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका गया। इसके बाद नेता विपक्ष आतिशी के साथ विधायक विधानसभा परिसर के बाहर 'जय भीम' के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आतिशी ने कहा- देश के इतिहास में पहली बार विधायकों को विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। एएपी के केवल एक विधायक अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद हैं। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा- शीशमहल की जांच होगी। पिछली सरकार की तरफ से फॉलोअप नहीं होने की वजह से कई प्रोजेक्ट्स की लागत दोगुनी हो गई है।

हम 2000 करोड़ रुपए के शराब नीति घोटाले पर सदन में चर्चा करेंगे। इधर, विधानसभा में आज कैग से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स पेश की जा सकती हैं।

भगवान महाकाल की महापूजा के बाद चढ़ा सेहरा

101 लीटर दूध से हुआ महाअभिषेक, साल में पहली बार 12 बजे होगी भस्म आरती

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के दौरान रातभर चली चार प्रहर की महापूजा के बाद गुरुवार को भगवान ने साल में एक बार धारण किया जाने वाला सवा मन का पुष्प मुकुट (सेहरा) पहना। सेहरा दर्शन के बाद दोपहर 12 बजे साल में एक बार होने वाली भस्म आरती होगी। इसके बाद भोग आरती होगी और शिव नवरात्रि का पारणा किया जाएगा।

बुधवार को महाशिवरात्रि महापर्व की मध्यरात्रि 11 बजे से गुरुवार सुबह तक श्री महाकालेश्वर की चार प्रहर की महाअभिषेक पूजा की गई। इसके बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाए गए और सप्तधान्य से उनका मुख मंडल श्रृंगारित किया गया। सुबह 6 बजे सेहरा आरती की गई। शाम को पूजन, आरती और शयन आरती के बाद महाकालेश्वर के पट 44 घंटे बाद बंद होंगे।

महाशिवरात्रि के अवसर पर महाभिषेक 101 लीटर दूध समेत दही, शक्कर, शहद, घी, फलों के रस, गन्ने के रस, गंगाजल, गुलाब जल, भांग और केसर मिश्रित दूध से किया गया। इसके बाद उन्हें जल से स्नान कराया गया।

भगवान महाकाल को 108 किलो सप्तधान अर्पित– महाभिषेक के बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाए गए और सप्तधान्य से उनका मुखारविंद श्रृंगारित किया गया। इनमें 31 किलो चावल, 11-11 किलो मूंग, तिल, मसूर, जौ, गेहूं, साल और उड़द अर्पित किए गए।

हिंदी ने उत्तर भारत की 25 भाषाओं को किया खत्म

सीएम स्टालिन ने कहा-तमिलनाडु में ऐसा नहीं होने देंगे

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में हिंदी बनाम तमिल की जंग छेड़ने वाले सीएम एमके स्टालिन लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। अब उन्होंने फिर से दोहराया है कि हम हिंदी को तमिलनाडु पर थोपने का विरोध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी के चलते उत्तर भारत की 25 से ज्यादा भाषाओं को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु हिंदी भाषा को 'थोपने' की इजाजत नहीं देगा और उन्होंने तमिलों एवं इसकी संस्कृति की

रक्षा करने का संकल्प जताया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित एक पत्र में उन्होंने कहा, 'हम हिंदी थोपने का विरोध करेंगे। हिंदी मुखौटा है, संस्कृत छिपा हुआ चेहरा है।' डीएमके ने आरोप लगाया है कि केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में तीन-भाषा फार्मूले के माध्यम से हिंदी को थोपने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है। पत्र में स्टालिन ने दावा किया कि उत्तर भारतीय भाषाओं को हिंदी ने नष्ट कर दिया है।'

अंडरग्राउंड केबिल बिछाने में खोदी गई सड़कों की तुरंत मरम्मत करें, राज्यमंत्री ने दिये निर्देश

भोपाल (नप्र)। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने एमपीईबी के अधिकारियों से कहा कि बिजली की अंडरग्राउंड केबिल बिछाने में खोदी गई सड़कों की तुरंत मरम्मत करें। श्रीमती गौर ने कल्पना नगर, शिव नगर फेस-1 और फेस-2 वार्ड 73 के पार्षद श्री राजू राठौर की शिकायत पर निर्देश दिये। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि खोदी गई सड़कों की मरम्मत को एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें।

पीथमपुर में ही जलेगा भोपाल गैसकांड का जहरीला कचरा

- सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार, पहला ट्रायल आज
- रामकी फैक्ट्री के पास 24 थानों की फोर्स है तैनात

पीथमपुर (नप्र)। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के रासायनिक कचरे को पीथमपुर में जलाने से रोकने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा की याचिकाकर्ताओं के सभी पक्षों को हाईकोर्ट ने सुन लिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट के इस रुख के बाद पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के निष्पादन का ट्रायल कल से शुरू होगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम रामकी एनवायरो कंपनी में मौजूद है। फैक्ट्री में कचरा जलाने का दूसरा ट्रायल 4 मार्च और तीसरा 12 मार्च से शुरू होगा। इधर, कचरा जलाने के ट्रायल को लेकर प्रशासन सतर्क है। 3 जनवरी को हुए विरोध को देखते हुए प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है।

लिहाजा, इंदौर देहात और धार जिले के 24 थानों से 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पीथमपुर में रामकी एनवायरो फैक्ट्री के पास तैनात किए गए हैं। गैस राहत विभाग के डायरेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि यूका के रासायनिक कचरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगी थी। जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की डबल बेंच ने पहले नंबर इस केस की सुनवाई की।

महाराष्ट्र की राजनीति में बदल रहे हैं समीकरण !

शिंदे नाराज, उद्धव कर रहे हैं फडणवीस की तारीफ

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। जिससे राज्य में बदलाव की सुगबुगाहट हवा बहने लगी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ और एनसीपी (शरद पवार) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से हुई मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इसके पहले हाल में ही एक कार्यक्रम में

पीएम मोदी और शरद पवार का करीब आना भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति की भारी जीत के बाद विपक्ष सदमे में चला गया था। मुख्यमंत्री बने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के दोनों सहयोगी दलों शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) को साध के रखा हुआ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और भारत रत्न नानाजी देशमुख को दी श्रद्धांजलि

भोपाल(नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्र ऋषि भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'एक्स' पर इन महान विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि इनका जीवन हर देशभक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित चंद्रशेखर आजाद का जीवन ऊर्जा, संकल्प और सेवा का अप्रतिम अध्याय है। मैं उन्हें बारम्बार नमन करता हूँ। उन्होंने कहा कि आजाद का बलिदान देश के युवाओं को सदैव राष्टभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और समाज सुधारक राष्ट्र ऋषि भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, गरीब कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के प्रति नानाजी देशमुख जी के विचार और कृतित्व राष्ट निर्माण के आधार हैं और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. नानाजी देशमुख ने ग्रामीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। उन्होंने ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए जीवन पर्यन्त काम किया और समाजसेवा को ही अपना ध्येय बनाया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चित्रकूट में 'नवीनीकृत प्रकल्प राम दर्शन' के लोकार्पण समारोह को संबोधित किया।

मणिपुर सीएम की रेस में 3 नाम, तीनों मैतेई

समर्थन में समुदाय के 22 एमएलए, कोई और मंजूर नहीं

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर में भाजपा एक बार फिर से मैतेई कम्युनिटी के नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। सूत्रों ने बताया कि सीएम की रेस में तीन नाम आगे चल रहे हैं। तीनों मैतेई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय के हैं। हालांकि, कुकी के साथ भाजपा के कई मैतेई विधायक अब उनके खिलाफ हैं। मणिपुर में कुकी-मैतेई के बीच 3 मई 2023 से हिंसा हो रही है। बीरेन सिंह पर हिंसा के दौरान मैतेइयों को कुकी के खिलाफ उकसाने के आरोप हैं। 9 फरवरी को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नए सीएम के नाम पर विधायकों में सहमति नहीं बनने पर केंद्र ने 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राज्य में अभी विधानसभा भंग नहीं हुई है।

ऐसे में भाजपा 10 मार्च से पहले सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। 60 सीटों वाले मणिपुर विधानसभा में भाजपा के 37 विधायक हैं। इनमें 27 मैतेई, 6 कुकी, 3 नगा और 1 मुस्लिम हैं। एनडीए के कुल 42 विधायक हैं। इसमें नेशनल पीपल्स फ्रंट के भी 5 विधायक शामिल हैं। मैतेई भाजपा विधायक बोले- तीनों में सत्यब्रत पहली पसंद बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मैतेई गुट के भाजपा विधायक दो खेमे में बंट गए हैं।

एक गुट बीरेन सिंह को फिर से सीएम बनाने के समर्थन में है तो दूसरा इसके खिलाफ। एंटी बीरेन कैंप के कई भाजपा

विधायक इंफाल के होटलों में डेरा डाले हुए हैं। इनमें संगाई कॉन्टिनेंटल होटल में रुके एक मैतेई भाजपा विधायक ने नाम न बताने की शर्त पर भास्कर को बताया, ज्यादातर विधायकों के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर थोकचोम सत्यब्रत सिंह, युमनाम खेमचंद सिंह और थोकचोम राधेश्याम सिंह के नाम पर चर्चा हो रही है। 22 विधायक इनके समर्थन में हैं। तीनों में टी सत्यब्रत हमारी पहली पसंद हैं। इसके जवाब में विधायक ने कहा,हम उनका समर्थन कभी नहीं करेंगे। हम उनकी तानाशाही के खिलाफ हैं।

सीएम नोहटा में श्री नोहलेश्वर महोत्सव में उज्जैन से वीसी से हुए सम्मिलित

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दमोह के नोहटा में नोहलेश्वर महोत्सव में श्री महाशिवरात्रि महापर्व पर उज्जैन से देर रात 11.15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान शिव और शक्ति के महापर्व महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आदि और अंत महादेव है। सुंदर और सत्य महादेव है। सृजन और संहार महादेव है। सनातन के आधार महादेव है और हमारे महादेव की शक्ति हैं आदिशक्ति जगदंबा माता पार्वती। मैं गौरीशंकर के चरणों में शीश झुकाता हूं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं भगवान श्री महाकाल महाराज की उज्जयिनी से नोहटा में विराजे भगवान श्री नोहलेश्वर महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी कृपा हुई भगवान भोलेनाथ की मुझ पर कि आज श्री नोहलेश्वर महाराज ने भी मुझे अपनी शरण में बुलाया और बाबा महाकाल ने भी। भगवान श्री शिव की कृपा से मध्यप्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन हुआ है। आपके आशीर्वाद से हम मध्यप्रदेश की प्रगति का नया अध्याय लिख रहे हैं। विरासत को सहेज कर विकास का रथ दौड़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि बहुत समय से सभी की इच्छा थी कि यहां महाशिवरात्रि महापर्व पर महोत्सव का आयोजन हो। बेहद प्रसन्नता की बात है कि इस बार 10 दिन का महोत्सव आयोजित हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दमोह से धर्मस्व ,पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी,दमोह सांसद श्री राहुल सिंह लोधी उपस्थित रहे।

भोपाल रेलवे स्टेशन पर 'किलाबंदी'

बिना टिकट सफर करने पर 218 यात्री पकड़े, 1.21 लाख का जुर्माना

भोपाल (नप्र)। भोपाल रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिए 'किलाबंदी' की गई। इस दौरान ऐसे 218 यात्री पकड़े गए, जिनके पास टिकट नहीं मिले। उनसे 1 लाख 21 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।

भोपाल स्टेशन पर सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक दो सुपरवाइजर समेत 20 टिकट चेकिंग स्टाफ ने 'किलाबंदी' टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन के बाहर निकलने वाले रास्तों की घेराबंदी की गई। ताकि कोई भी यात्री बिना जांच के स्टेशन के बाहर न जा सकें।

28 गाड़ियों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग- कार्रवाई के दौरान स्टेशन पर आने-जाने वाली कुल 28 गाड़ियों के यात्रियों के टिकट की जांच की गई। जांच के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले कुल 110 यात्री पकड़े गए। जिनसे 68 हजार 605 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले कुल 105 यात्री पाए गए। जिनसे 52 हजार 300 रुपए वसूले गए।

बिना बुक कराए सामान लेकर यात्रा कर रहे एवं स्टेशन पर गंदगी फैलाते हुए 3 यात्री मिले। इन पर 450 रुपए का जुर्माना किया गया।

ट्रेनों के अंदर भी चेकिंग की गई- कार्रवाई के दौरान ट्रेनों के अंदर भी चेकिंग की गई। इस दौरान यात्रियों से उनके टिकट मांगें गए। जो यात्री बिना टिकट के सफर कर रहे थे, उन पर जुर्माने की कार्रवाई हुई।

मासूम से बैड टच का आरोपी जेल गया

बोला- बच्ची को अकेला देख नीयत खराब हुई, अब भी सदमे में है पीड़िता

भोपाल (नप्र)। भोपाल के गांधी नगर थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम से बेड टच करने वाले अधेड़ आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बच्ची को अकेला देखकर उसकी नीयत खराब हो गई थी। नशे में होने के कारण उसने बच्ची को पकड़ लिया और उसके साथ गलत हरकत की।

आरोपी मजदूरी करता था। हालांकि उसने पूर्व में इस प्रकार की किसी भी वारदात को अंजाम देने की बात से इनकार किया है। पुलिस उसका पुराना रिकार्ड खंगाल रही है।

बच्ची के माता-पिता गए थे मजदूरी करने

गांधी नगर पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार शाम की है। बच्ची के माता-पिता मजदूरी के लिए घर से बाहर थे। नानी-नानी भी बाहर थे, जब परिजन घर आए तो बच्ची ने रोते हुए उन्हें बताया कि पड़ोस में रहने वाले अंकुर नाम के व्यक्ति ने उसे बेड टच किया है। बच्ची के परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्ची के बयान दर्ज कर लिए।

परिवार ने की सख्त कार्रवाई की मांग

बच्ची के परिवार ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि बच्ची अभी भी इस घटना से सदमे में है। उसे परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से बात करने में डर लग रहा है। पुलिस उससे पूछताछ भी जारी है।

किसान कल्याण मिशन बनेगा खेती को लाभ का धंधा बनाने का माध्यम

भोपाल(नप्र)। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि किसान कल्याण मिशन अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह मिशन कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का प्रमुख माध्यम बनेगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्राकृतिक कृषि के प्रसार एवं किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया गया है। प्राकृतिक खेती कर रहे एवं प्राकृतिक खेती के इच्छुक राज्य के किसानों के पंजीयन के लिए पोर्टल प्रारंभ किया गया है।पोर्टल पर प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक कुल 72 हजार 967 किसानों ने पंजीयन करवाया है। प्रत्येक पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केन्द्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 81 लाख से अधिक किसानों को गत वर्ष चार हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का अंतरण किया गया है। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को एक हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3 हजार 900 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है। शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस प्रदाय किया गया। देश में पहली बार राज्य सरकार ने सोयाबीन का 4 हजार 892 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का निर्णय लिया। लगभग 2 लाख किसानों से प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन कर 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया गया। खरीफ-2024 में 1.23 लाख क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज का वितरण किया गया। मध्यप्रदेश को कृषि उत्पादन में निरंतर अग्रणी स्थान मिला है। सात बार कृषि कर्मण अवॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से लागू है। कृषकों को सौर ऊर्जा के लाभ से लाभांवित करने के लिए प्रदेश में अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने वाले लगभग सवा

मध्यप्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति की ओर अग्रसर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश में वर्ष 2070 तक कार्बन फुट-प्रिंट को शून्य तक लाने और समाप्त होते जीवाश्म ईंधन के विकल्प तलाशने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (अक्षय) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्यप्रदेश पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ योगदान दे रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 12 वर्षों में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 14 प्रतिशत अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे अब कुल ऊर्जा उत्पादन में सहभागिता 30 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

रीवा और ओंकारेश्वर: हरित ऊर्जा के नए केंद्र- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने उद्बोधन मे कहा जीआईएस के शुभारंभ पर मध्यप्रदेश का रीवा सोलर पार्क देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्कों में से एक है। इसके साथ ही हाल ही में ओंकारेश्वर में देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट का शुभारंभ किया गया है, जिससे अक्षय ऊर्जा उत्पादन को नई दिशा मिली है।

मध्यप्रदेश : ऊर्जा सरप्लस राज्य-

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण देश के अग्रणी ऊर्जा सरप्लस राज्यों में से एक है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्म निर्भरता को प्राथमिकता देते हुए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है।

तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने वाली पहली नवकरणीय ऊर्जा नीति- मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लागू की है। इस नीति में सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को अनुकूल और लचीले अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नया आयाम जुड़ रहा है।

सांची बना मध्यप्रदेश का पहला सौर शहर- पर्यावरण संरक्षण और नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, सांची को राज्य का पहला सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह 'नेट ज़ीरो कार्बन' सिद्धांत पर आधारित होगा, जिसमें जितनी ऊर्जा का उपभोग होगा, उतनी ही हरित ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। यह परियोजना देश-दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनेगी।

नर्मदापुरम में नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए समर्पित निर्माण क्षेत्र- राज्य सरकार नर्मदापुरम जिले में पॉवर और नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए एक समर्पित निर्माण ज़ोन विकसित कर रही है, जिससे राज्य में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा का व्यापक निवेश

जीआईएस-भोपाल में मध्यप्रदेश की टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के कारण नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जीआईएस-भोपाल के उद्घाटन अवसर पर कहा कि विगत दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 70 बिलियन डॉलर (5 ट्रिलियन रुपये से अधिक) का निवेश किया गया, जिससे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस विकास में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और बताया कि राज्य वर्तमान में लगभग 31,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता रखता है, जिसमें से 30 प्रतिशत हरित ऊर्जा है।

वर्ष- 2030 तक 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की दूरदर्शी नीतियों और राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से मध्यप्रदेश हरित ऊर्जा हब के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में राज्य में 5 बड़ी सौर परियोजनाएँ कार्यरत हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 2.75 गीगावाट (2,750 मेगावाट) है। सरकार की योजना वर्ष-2030 तक नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 20 गीगावाट (20,000 मेगावाट) करने की है।

नवकरणीय ऊर्जा में 5.72 लाख करोड़ से अधिक का निवेश एवं 1.4 लाख से अधिक रोजगार के अवसर

मध्यप्रदेश सरकार नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 5,21,279 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित कर रही है, जिससे 1,46,592 नौकरियाँ सृजित होंगी। जीआईएस-भोपाल में नवकरणीय ऊर्जा सेक्टर में अवाडा एनर्जी, एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एक्सिस एनर्जी वेंचर, एनएसएल रिन्यूएबल पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, टोरेंट पॉवर और जिंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इस निवेश से राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को गति मिलेगी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मध्यप्रदेश- भारत के 'नेट ज़ीरो कार्बन' लक्ष्य में प्रमुख योगदानकर्ता

राज्य सरकार की यह पहल भारत के 'नेट ज़ीरो कार्बन' लक्ष्य वर्ष-2070 को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मध्यप्रदेश तेजी से नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में देश का नेतृत्वकर्ता बन रहा है और आत्मनिर्भर भारत व स्वच्छ ऊर्जा मिशन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

11 नंबर मार्केट के रेस्टोरेंट में आग

सिलेंडर लीकेज होने से आग भभकी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में लगातार दूसरे दिन गैस सिलेंडर लीकेज होने और फिर आग लगने की घटनाएं हुईं। बाग सेवनिया स्थित संत आसाराम फेस-1 में बुधवार को एक ही परिवार के 11 सदस्य झुलस गए थे, जबकि गुरुवार को 11 नंबर मार्केट स्थित एक रेस्टोरेंट में भी गैस से भरे सिलेंडर में आग लग गई। गनीमत रही कि समय पर आग बुझा दी गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

पहली घटना बुधवार को आसाराम फेस-1 में हुई थी। यहां शिवरात्रि की पूजा के दौरान यह घटना हुई। किचन में रखा सिलेंडर लीकेज होने लगा, जो घर में फैल गई। इस वजह से आग लग गई। जिससे घर के मालिक नवल किशोर शुक्ला उम्र 55 वर्ष, उनकी मां मनोरमा शुक्ला उम्र 80 वर्ष, पत्नी मोनिका शुक्ला उम्र 44 वर्ष, बेटे राकेश शर्मा उम्र 35 वर्ष, बेटी श्रीधा उम्र 15 वर्ष समेत प्रभा किशोर शुक्ला उम्र 70 वर्ष, चंदेश त्रिपाठी उम्र 34 वर्ष और सुरेंद्र उचेनिया झुलस गए।

विधानसभा में क्लर्क हैं शुक्ला

नवल किशोर शुक्ला विधानसभा में क्लर्क हैं। शिवरात्रि के दिन उन्होंने अपने घर पर पूजा का आयोजन किया था। जिसके चलते उनका पूरा परिवार मौजूद था। पूजा के दौरान घर के किचन में खाना बन रहा था। इतने में गैस के सिलेंडर से गैस लीक होने लगी। इसके बाद उन्होंने गैस सिलेंडर बदल दिया और सिलेंडर को घर में ही रख दिया। बावजूद सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी। पूजा के दिए की वजह से घर में फैली गैस ने आग पकड़ ली और सदस्य झुलस गए। पड़ोसियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड और पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मीडिया और सिनेमा की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका : राज्यमंत्री श्रीमती गौर

भोपाल (नप्र)। मीडिया और सिनेमा की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। फिल्में समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। हमारी फिल्में केवल कथा और कहानी नहीं होतीं, इनमें राष्ट्र और समाज को सशक्त करने का संदेश भी होता है। आज के डिजिटल युग में मीडिया और सिनेमा की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर सेज विश्वविद्यालय के सभागार में सतपुड़ा चलचित्र समिति के ग्वालियर शार्ट फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर विमोचन समारोह को संबोधित कर रही थी।

राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि ग्वालियर शार्ट फिल्म फेस्टिवल में युवा भाग लेगें और अपनी रचानात्मक और सृजनात्मक क्षमता से नवाचार करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें युवा पीढ़ी पर गर्व है। युवा वर्ग देश में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि युवाओं की समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि फिल्मों के माध्यम से सामाजिक मूल्यों, परम्पराओं और संस्कृति को संरक्षित करने के साथ ही समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। सतपुड़ा

चलचित्र समिति इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा ने हमारे राष्ट्रवाद, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विविधता को सशक्त किया है। उन्होंने कहा कि सिनेमा को समाज से जोड़ने का माध्यम बनाने की दिशा में समिति का प्रयास सराहनीय है। मंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि आज के युग में कुछ डिजिटल प्लेटफार्म पर असामाजिक व्यक्ति परिवारिक मूल्यों को नष्ट करने का दुष्प्रयास कर रहे है। ऐसे समय में सतपुड़ा चलचित्र समिति जैसी संस्थाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर शार्ट फिल्म फेस्टिवल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक विचारधारा का विस्तार है। यह नवोदित फिल्मकारों के लिये एक मंच है। इस फेस्टिवल के माध्यम से हम ऐसे सिनेमा को प्रोत्साहित करेगें जो भारतीय मूल्यों को संरक्षित रखते हुए समाज के समक्ष सार्थक विषय प्रस्तुत कर रहे हैं।

ग्वालियर शार्ट फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर विमोचन समारोह के प्रारंभ में सतपुड़ा चलचित्र समिति और विश्व संवाद केन्द्र मध्यप्रदेश के अध्यक्ष श्री लाजपत आहूआ ने कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सेज विश्वविद्यालय के कुलाधिसचिव श्री नीरज उपमन्यु ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। उन्होंने अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।

किसानों को उपार्जित गेहूं का भुगतान समय पर करें

प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती शमी ने की समीक्षा

भोपाल (नप्र)। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सागर एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर एवं कलेक्टर्स से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों से अच्छी गुणवत्ता का गेहूं उपार्जित करें। साथ ही उपार्जित गेहूं का भुगतान समय पर करें। गौरतलब है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने गत दिनों गेहूं उपार्जन की समीक्षा के दौरान जिलेवार उपार्जन तैयारियों की समीक्षा के निर्देश दिये थे।

श्रीमती शमी ने कहा कि उपार्जन केन्द्रों में किसानों के लिये सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किसानों को गेहूं उपार्जन के लिये पंजीयन कराने के लिये जागरूक करें। उन्होंने संभागायुक्त और जिलों के कलेक्टर्स से अलग-अलग बात कर गेहूं उपार्जन के लिये की गई तैयारियों की जानकारी ली। अभी तक 3 लाख से अधिक किसान गेहूं उपार्जन के लिये पंजीयन करा चुके हैं। श्रीमती शमी ने बताया कि वेयर हाउस के लंबित भुगतान भी जल्द किये जायेंगे। उन्होंने उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का ई-केवायसी कराने के निर्देश भी दिये। उन्होंने बताया कि गेहूं उपार्जन के लिये किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं का उपार्जन 1 मार्च से 18 अप्रैल तक होगा। शेष संभागों में 17 मार्च से 5 मई तक गेहूं का उपार्जन किया जायेगा।

संचालक खाद्य श्री कर्मवीर शर्मा ने कहा कि उपार्जित गेहूं का परिवहन जल्द किया जाये। गेहूं के भंडारण की समुचित व्यवस्था करें। उपार्जन केन्द्रों की माइक्रो प्लानिंग करें। इस बात ध्यान रखें कि उपार्जन केन्द्रों में किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों का सत्यापन कराएं। उचित मूल्य दुकान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन 7 दिन में करा लें। उपार्जन कार्यों की मॉनिटरिंग के लिये संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं। उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था करें। एमडी नागरिक आपूर्ति निगम श्री अनुराग वर्मा ने किसानों के रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया। उन्होंने धान मिलिंग की समीक्षा की तथा मिलिंग का कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिये। श्री वर्मा ने परिवहन संबंधी लंबित बिलों को जल्द भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भुगतान की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। जिला कलेक्टर्स ने गेहूं उपार्जन संबंधी तैयारियों की जानकारी दी।

शुरु हुई 10वीं की परीक्षा

9.53 लाख स्टूडेंट्स हुए शामिल ; भोपाल में बने हैं 103 एग्जाम सेंटर

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। पहला पेपर हिंदी का रहा। पूरे प्रदेश में 9.53 लाख से अधिक स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल हुए है। प्रदेश में 3887 और भोपाल में 103 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं।

इससे पहले 24 फरवरी से कक्षा 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसका पहला पेपर भी हिंदी का था, जबकि शुक्रवार को दूसरा परचा अंग्रेजी का रहेगा। बोर्ड ने अबकी बार परीक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव और सख्त नियम लागू किए हैं। जिनका पालन सभी छात्रों और परीक्षा केंद्रों से कराया जा रहा है। एग्जाम देकर लौटे स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर अच्छा गया। परीक्षा केंद्र के अंदर पेपर टाइम से दिया गया और हमें आंसर शीट भरने में भी सहयोग किया गया। हमने पेपर अच्छे से किया है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि उन्होंने सारे सवाल किए लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी रहे, जो वह नहीं कर पाए।

सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू हुई

परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हुई, जो दोपहर 12 बजे तक चली। इस बार, छात्रों को केवल 32 पृष्ठों की मुख्य उत्तर पुस्तिका प्रदान की गई है। अतिरिक्त सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी। इसलिए छात्रों को अपने उत्तर संक्षेप में और सटीक रूप से लिखने की सलाह दी गई।

16 लाख से अधिक विद्यार्थी दे रहे परीक्षा

इस साल हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) परीक्षा में 9 लाख 53 हजार 777 छात्र एवं हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) परीक्षा में 7 लाख 6 हजार 475 छात्र शामिल हो रहे हैं। कुल परीक्षार्थियों की संख्या 16 लाख 60 हजार 252 है। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 3,887 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

ईमानदारी की पेटी रखी जाएगी परीक्षा केंद्रों पर

इस बार परीक्षा केंद्रों पर 'ईमानदारी की पेटी' नामक अनोखी पहल की गई है। मंडल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर लोहे की एक पेटी रखी जाएगी, जिसमें छात्र अपनी स्वेच्छा से किसी भी प्रकार की नकल सामग्री, जैसे गाइड, चिट आदि डाल सकेंगे। इस पेटी पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि यह पेटी स्वेच्छा से नकल सामग्री परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले जमा करने के उद्देश्य से रखी गई है। यदि कोई छात्र परीक्षा कक्ष में नकल सामग्री के साथ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ परीक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

समिट सफल, बड़ी चुनौती आगे

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार द्वारा भोपाल में आयोजित दो दिनी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस मायने में सफल रही कि इसमें अब तक की सभी समिटों में आए निवेश प्रस्तावों की तुलना में रिकॉर्ड 30.77 लाख करोड़ रू. के निवेश प्रस्ताव आए। जिनमें कुछ विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। ये प्रस्ताव राज्य में अब तक हुई सभी समिटों के प्रस्तावों की कुल राशि से कुछ ही कम हैं। बतौर एक मेगा इंवेंट सरकार ने इसका सफल आयोजन किया, लेकिन असली और बड़ी चुनौती इन निवेश प्रस्तावों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारने की है। इन प्रस्तावों के फॉलो अप की है, जोकि अब तक की समिटों का सबसे कमजोर पक्ष रहा है। ज्यादातर मामलों में तो यह देखा गया है कि उद्योगपति उद्योग लगाने के नाम पर सरकार से नाममात्र की दर पर जमीनें लेकर उन पर बैंकों से कर्ज लेकर बैठ जाते हैं। कर्ज का यह पैसा भी कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाता है और प्रदेश उद्योग और उनसे मिलने वाले रोजगार की प्रती क्षा ही करता रहता है। इसके अलावा सरकारी तंत्र का रवैया भी अक्सर बहुत ज्यादा उद्योग फ्रेंडली नहीं होता। ऐसे में उद्योगपति भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद भी वैसा ही कुछ न हो, इसकी सावधानी सरकारी विभागों को बरतनी होगी। हालांकि समिट में मुख्य सचिव ने कहा कि आइंदा हमारे अधिकारी ही उद्योगपतियों को फॉलो करेंगे। कहा जा रहा है कि इस समिट में आए प्रस्तावों में से चौथाई भी क्रियान्वित हो गए तो मप्र की आर्थिक सूरत ही बदल जाएगी। फिलहाल दावा किया गया है कि इन सभी प्रस्तावों पर अमल हुआ तो राज्य में 21 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। समिट में आए निवेश प्रस्तावों में भी भौगोलिक विसंगति है। क्योंकि जो निवेश प्रस्ताव आए हैं, वो मुख्यतः इंदौर, देवास, भोपाल, जबलपुर और रीवा क्षेत्र के लिए ही हैं। बुंदेलखंड और चंबल में तो बहुत मामूली निवेश के प्रस्ताव हैं। जबकि राज्य के 21 जिलों के लिए तो कोई भी प्रस्ताव समिट में नहीं आया है। यह वाकई चिंता की बात है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि राज्य के बड़े हिस्से में अभी भी औद्योगीकरण के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हुआ है। अगर राजधानी भोपाल की ही बात की जाए तो यहां अभी भी एयर कनेक्टिविटी बहुत कम है। भोपाल सभी प्रदेशों की राजधानियों से नहीं जुड़ा है। ग्लोबल समिट जैसा बड़ा आयोजन करने के लिए यहां कोई बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी नहीं है। यानी अभी काफी कुछ करना बाकी है। इसमें शक नहीं कि राज्य में निवेश लाने के लिए मोहन यादव सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि यह हमारे लिए एक मिशन है। मप्र की अनुकूलताओं को हम दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से रख रहे हैं। इसके अपेक्षित नतीजे जरूर आएंगे। राज्य सरकार ने रीजनल इन्वेस्टर्स समिट भी शुरू की हैं, जिनका प्रतिसाद अच्छा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को मुंबई और दिल्ली की तरह विकसित किया जाएगा, वहीं प्रदेश के अन्य शहरों को इंदौर की तरह विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन की तरह विकसित किया जाएगा। ये घोषणाएं भी हकीकत में कब तक और किस तेजी से बदलती हैं, इस पर प्रदेशवासियों की नजर रहेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे मेगा इंवेट केवल राजनीतिक लाभ के आयोजन बनकर न रह जाएं, यह देखना भी जरूरी है। वरना पुराना अनुभव यही रहा है कि समिट में आए निवेश प्रस्तावों में से सिर्फ 10 फीसदी ही जमीन पर उतरे हैं।

नजरिया

सुरेश पचौरी
लेखक भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं।

सनातन धर्म की गौरव प्रतिष्ठा का प्रतीक आयोजन महाकुंभ

माघे मासे गंगे स्नानं यः कुरुते नरः ।
युगकोटिसहस्राणि तिष्ठंति पितृदेवताः।।

स्कंद पुराण में उल्लेख है कि माघ मास में गंगा में स्नान करने वाले व्यक्ति के पितर युगों-युगों तक स्वर्ग में वास करते हैं। कितना ही बिरला अवसर है कि प्रयागराज में संगम किनारे श्रद्धा का महाकुंभ आयोजित हुआ और सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई। यूं तो यह आयोजन सदियों से चला आ रहा है लेकिन इस वर्ष इस आस्था को सम्मान देने में भाजपा की सरकारों का अथक योगदान भी रहा है। महाकुंभ जैसे महाआयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं का सुचारू रूप से प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस कुशलता से इस वृहत्तर दायित्व को संभाला है वह वर्षों तक सराहना के साथ याद किया जाएगा। धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण के इस अद्भुत आयोजन ने ऐसा संगम रचा जो कल्पनातीत है। सुरक्षा, सुविधाएं और सुगमता प्रदान करने के जतन के साथ ही साथ इस आयोजन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के विशेष प्रयास हुए यह स्तुत्य है। इन प्रयासों ने महाकुंभ को केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकरों के प्रति चेतना का संदेश भी दिया।

हमारी भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा में कुंभ पर्व सहस्राब्दियों से श्रद्धा, आस्था और ज्ञान की साधना का पर्व रहा है। भगवान आदि शंकराचार्य ने भारतीय जनमानस में धर्म की भावना जगाने और संस्कृति की चेतना मजबूत करने के लिए देश के चार कोनों पर चार मठ बनाये। पूर्व में जगन्नाथपुरी पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में जोशीमठ तथा दक्षिण में श्रंगेरी मठ। आदि शंकराचार्य जी ने देश की चार प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, क्षिप्रा व गोदावरी के तट पर चार शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में चार कुंभ-मेलों के आयोजन की रूपरेखा रची। कुंभपर्व का आधार खगोलीय घटना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहों की गति और उनके मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कर कुंभ मेलों के आयोजन की तिथियां और स्थान तय होते है। 12 साल के अंतराल से सूर्य और गुरू की राशि विशेष में स्थिति कुंभ पर्व का समय और स्थल निर्धारित करते है।

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में उल्लेख किया है- 'माघ मकरगत रवि जब होई। तीरथ पतिहि आव सब कोई' अर्थात् मकर राशि में सूर्य एवं वृषभ राशि में गुरू का प्रवेश होता है तब तीर्थ राज प्रयाग में कुंभ पर्व आयोजित होता है।

कुंभ को लेकर पौराणिक आधार भी है। देवताओं और दानवों ने समुद्रमंथन किया। इस मंथन में अमृत निकला। अमृत के बंटवारे की छीना छपटी में अमृत कलश से कुछ बूंदे छलकी। ये अमृत बूंदे प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरीं। इन शहरों के

पास से बहने वाली नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, एवं क्षिप्रा अमृतमयी हो गई। इन्ही स्थलों पर कुंभपर्व आयोजित किया जाता है।

कुंभ पर्व नदियों के महत्व का महापर्व है। यह विविधता में एकता प्रदर्शित करने में केन्द्रीय भूमिका निभाता है। कुंभ पर्व 'वसुधैव कुटंबकम' की भावना को साकार करता है। यह आयोजन सर्वसमावेशी संस्कृति एवं भारतीय चिंतन की वैज्ञानिकता का प्रतीक है। कुंभ महापर्व हमें आत्मशुद्धि, परोपकार एवं सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। महाकुंभ के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन दर्शन को वैश्विक पहचान मिली है। कुंभ पर्व भारतीय संस्कृति की गहराई, सहिष्णुता और एकता का अद्भुत संगम है। यह पर्व केवल स्नान का पर्व नही है बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने आत्मचिंतन करने और मानवता के प्रति समर्पण व्यक्त करने का अवसर है। भारतीय सनातन परंपरा में यह आयोजन अनूठी आस्था, संस्कृति और दर्शन का सदियों से परिचायक रहा है और आगे भी रहेगा। इस वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ अपने आयोजन के आरंभ से ही अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता रहा है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक लगभग 45 दिन चलने वाले कुंभ महापर्व की छंटा ही निराली रही है। प्रतिदिन औसतन 1.5 करोड़ लोग कुंभ में गंगा स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। देश ने सनातन की ऐसी जबरदस्त ताकत पहले कभी नहीं देखी। विश्व चकित है। पूरी दुनिया अचरज से सनातन संस्कृति की प्रस्फुटित होती इस शक्ति को समझने की कोशिश कर रही है। महाकुंभ के भव्य दृश्यों ने हमें हतप्रभ किया है और अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के प्रति गहन आस्था और गौरव से भर दिया है।

महाकुंभ का संपूर्ण मानवता को स्पष्ट संदेश है कि आस्था और आध्यात्म में कोई भेद नहीं होता। यहां कोई भी जाति या वर्ग का भेद नहीं होता। यहां राजा हो या रंक, साधु हो या गृहस्थ सब मां गंगा की गोद में पुण्य अर्जित करने आते है। यह समरसता ही कुंभ की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रयागराज का कण-कण अलौकिकता का स्मरण कराता है। त्रिवेणी स्नान के दौरान जो शांन्ति और दिव्यता का अनुभव होता है उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। महाकुंभ में स्नान केवल धार्मिक कार्य मात्र नही है, बल्कि आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। महाकुंभ में आकर यह अनुभव होता है कि सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की एक महान परंपरा है। साधु संतों के प्रवचन मंत्रों की ध्वनि अखाड़ों की भव्यता और गंगा आरती का सौन्दर्य मन में ईश्वरीय अनुभूति कराता है।

मेरे लिए वे असीम शांति और गौरव के पल थे जब मैंने पुण्य भूमि प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम में स्नान कर मां गंगा की पूजा-अर्चना कर अपनी आस्था प्रकट की। किसी भी श्रद्धालु की तरह मेरे लिए भी यह असीम आनंद के क्षण थे। गंगा तटों पर गूंजती मंत्रध्वनियां, हवनकुडों से उठती धूप की सुवास आयोजन को दिव्यता प्रदान करती है। इस संकल्पना के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व स्तुत्य और स्मरणीय है। मैंने अनुभव किया कि गंगा मैया में लगाई गई हर डुबकी एक अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाती हैं। आत्मा निर्मल होकर परमतत्व से साक्षात्कार करती है। इसी साक्षात्कार के उपरांत यह कह सकता हूं कि 2025 का प्रयागराज महाकुंभ एक आयोजन ही नहीं अपितु सनातन की जीवंत धरोहर बनकर प्रकट हुआ है।

इस दिव्यता को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के कथन में भी अनुभूत किया जा सकता है। प्रयागराज में गंगा स्नान के उपरांत यशस्वी एवं तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'प्रयागराज में महाकुंभ में आकर धन्य हो गया। संगम पर स्नान एक दिव्य जुड़ाव का क्षण है और इसमें भाग लेने वाले करोड़ों अन्य लोगों की तरह मैं भी भक्ति की भावना से भर गया। मां गंगा सभी को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद दें।'

प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रार्थनाओं में हमारी प्रार्थना के स्वर भी शामिल हैं। यशस्वी एवं तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सभी सनातनधर्मियों को नया गौरव प्राप्त हुआ है। उनके शासनकाल में हमारी आस्था के प्रतीकों और धार्मिक स्थलों का पुनरूत्थान हुआ है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के कार्य काल में अयोध्या में रामलला की प्राणप्रतिष्ठा, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरीडोर, महाकाल लोक परियोजना, केदारनाथ मंदिर एवं जगन्नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण जैसे श्रेष्ठतम कार्यों से भारत का सांस्कृतिक वैभव प्रतिष्ठित हुआ है तथा लोक आस्था के महत्व में अद्वितीय वृद्धि हुई है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का यह महाकुंभ उत्सव सभी के जीवन में नयी ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मेरा मानना है कि महाकुंभ 2025 के माध्यम से जागृत हुई सनातन की यह चैतन्य धारा राष्ट्रहित में प्रवाहित होकर एक नये भारत के निर्माण में सहायक होगी।

राजनीति

अवधेश कुमार
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भारतीय चुनावों में विदेशी भूमिका का सच

भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर यूएसएड या यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से 21 मिलियन डॉलर यानी 182 करोड रुपए आने की सूचना ने पूरे देश में खलबली पैदा की है। ट्रंप प्रशासन के अंदर नवनिर्मित डिपार्मेंट आफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोजे यानी सरकारी दक्षता विभाग ने उसकी जानकारी देते हुए सूची जारी की। आरंभ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोकने की घोषणा की और कहा कि भारत के पास स्वयं काफी रुपया है तो हम क्यों दे। उस समय ऐसा लगा मानो भारत द्वारा अमेरिकी सामग्रियों पर लगने वाले आयत शुल्क के विरुद्ध कदम उठा रहे हैं। फिर उन्होंने मियामी और उसके बाद वाशिंगटन डीसी के आयोजनों में कहा कि हमें भारत में मतदान बढ़ाने पर 21 मिलियन खर्च करने की आवश्यकता क्यों है? मुझे लगता है कि वे किसी और को जिताने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि रूस ने हमारे देश में 2 डॉलर का खर्च किया है तो यह हमारे लिए बड़ा मुद्दा बन जाता है। भारत सरकार की ओर से सूचना है कि जानकारियों के आधार पर जांच आरंभ हो गई है। हमारे देश की समस्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र व भाजपा की राज्य सरकारों के रहते जब भी ऐसी खबर आती है सोशल मीडिया और मीडिया पर प्रभाव रखने वाला बड़ा वर्ग इसे गलत साबित करने पर तुल जाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कह रहे हैं तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। हमारे पास भारतीय चुनाव में हस्तक्षेप को साबित करने के लिए सटीक प्रमाण नहीं हैं। कुछ तथ्यों के आधार पर इसकी विवेचना की जा सकती है। डोजे द्वारा यूएसएड की जारी सूची में 15 तरह के कार्यक्रम के लिए धन देने की बात है। इनमें एक दुनियाभर में 'चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण' के लिए 48.6 करोड़ डॉलर यानी 4200 करोड़ का अनुदान था। इसी में भारत की हिस्सेदारी 182 करोड़ रुपए की है। बांग्लादेश को मिलने वाली 251 करोड़ रुपए बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा था। विश्व में चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया के सुदृढ़िकरण की आवश्यकता अमेरिकी प्रशासन को क्यों महसूस हुई? बांग्लादेश में राजनीतिक सुधारों के लिए अमेरिकी सहायता राशि की जरूरत क्यों थी? मोजांबिक में पुरुष खतना कराएं, कंबोडिया में स्वतंत्र आवाज मजबूत हो तो प्राग में नागरिक समाज अंदर सशक्त हो इनका केवल समाज सेवा या उस देश का हित उद्देश्य नहीं हो सकता। इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं। सच है कि सन् 2012 में भारत के चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ एमओयू यानी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इन आरोपों और समाचारों को निराधार बताया है कि आईएफएससी से धन आयोग को स्थानांतरित हुआ था। कहीं नहीं कहा गया है कि इसने सीधे चुनाव आयोग को पैसा दिया। इस एजेंसी को यूएसएड से धन मिलता था और यह जार्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ संबद्ध है। ऐसी संस्थाएं किसी माध्यम से अपनी भूमिका को वैधानिकता का आवरण देने की दृष्टि से समझौते करती हैं और फिर अपने अनुसार कार्य करती है। ध्यान रखिए 2012 में महत्वपूर्ण गुजरात विधानसभा चुनाव था तथा उसके पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर का। 2013 में पहले कर्नाटक उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। भारतीय चुनावों और राजनीति में विदेशी भूमिका की बात पहली बार नहीं आई है। नरेंद्र मोदी सरकार गठित होने के बाद से इसका चरित्र और व्यवहार बदला है किंतु हमारे देश में यह बीमारी लंबे समय से है। जब देश के नेता नौकरशाही, बुद्धिजीवी, पत्रकार, एक्टिविस्ट आदि छोटे-छोटे लाभ के लिए खिलौना बनने को तैयार हो जाएं तो कुछ भी हो सकता है। शीतयुद्ध काल में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धायें थीं। दोनों अपने प्रभाव के लिए हस्तक्षेप करते थे। भारत में 1967, 77, 80 के चुनाव में विदेशी भूमिका की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। सोवियत संघ के विघटन के बाद मित्रोखिन पेपर नाम से ऐसी जानकारियां आईं जिनसे पढ़ने वाले भौचक रह गए थे। वासिली मित्रोखिन, जो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी से संबद्ध थे, और क्रिस्टोफ़र एन्ड्र्यूज ने अपनी पुस्तकों में खुलासा किया कि केजीबी ने भारत के अनेक समाचार पत्रों एक्टिविस्टों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, नेताओं पर उस समय अरबों खर्च किए। भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके डेनियल मोयनिहान ने पुस्तक ए डैंजरस प्लेस में लिखा है कि भारत में कम्युनिस्टों के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने भारतीय नेताओं को धन दिए।

सन् 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से अनेक ऐसी घटनाएं हुईं हैं जिनसे संदेह बढ़ा। 2019 में दोबारा उनके सत्ता में लौटने के बाद अलग तरह के स्वरुपों में आंदोलन हुए । इनमें नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध शाहीनबाग धरना और उसके समर्थन में देश और दुनिया में सोशल मीडिया से लेकर अन्य अभियान तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सरकार के विरुद्ध सीधे बयान देना शामिल है। कृषि कानून के विरुद्ध हुए आंदोलन में भी हमने देखा कि देश के बाहर से टूलकिट बनाकर अभियान चलाए जा रहे थे। इस तरह के आंदोलन भारत ने कभी देखे नहीं जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा नहीं हो, पर उग्रता और हठधर्मिता ऐसी कि मुख्य सड़क पर धरना दो, आवश्यकतानुसार निर्माण भी कर लो और बैठे रहो, किसी सूरत में हटो नहीं। यूएसएड द्वारा 2021 में भारतीय मिशन के प्रमुख के रूप में वीणा रेड्डी को भेजा गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उनका भारत का कार्यकाल समाप्त हो गया और वह वापस लौट गईं हैं। उस समय भी उनकी भूमिका को लेकर प्रश्न उठे थे।

विदेशी हस्तक्षेप की बातें भारत के अलावा दूसरे देशों और नेताओं द्वारा भी कहा जा रहा है। विश्व के अनेक देशों की चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में विदेशी शक्तियों और संस्थाओं की भूमिका सामने आती रही हैं। माइक्रोसाफ्ट ने डीपफेक और एआई के माध्यम से भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की कोशिशों पर चेतावनी दिया था। 2018 में अमेरिकी सीनेट ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए रूसी खुफिया एजेंटों ने फेसबुक विज्ञापनों के साथ कई तरीके से चुनावों को प्रभावित किया था। कनाडा और आस्ट्रेलिया के चुनावों में चीनी फंडिंग से चलने वाले अभियानों की भूमिका सामने आई। आस्ट्रेलिया में राजनीतिक संप्रभुता पर विदेशी हस्तक्षेप के प्रभाव पर व्यापक चर्चा हो रही है और इसे ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए गए हैं। सेबेस्टियन व्हाइटमैन की किताब 'द डिजिटल डिवाइड इन डेमोक्रेसी' में कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि चीनी सरकार के समर्थन से चीन की साइबर आर्मी आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों, दक्षिण कोरिया और भारत के चुनावों को प्रभावित कर सकती है। हांगकांग यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सहायक प्रोफेसर डोव एच लेविन ने 2020 में अपनी किताब किताब 'मेडलिंग इन द बैलेट बॉक्सः द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ पार्टिजन इलेक्टोरल इंटरवेंशन' में लिखा है कि 1946 से वर्ष 2000 के दौरान 938 चुनावों का परीक्षण किया गया। इनमें से 81 चुनावों में अमेरिका, जबकि 36 चुनावों में रूस ने हस्तक्षेप किया। इस तरह 938 में से 117 यानी हर 9 चुनाव में से 1 चुनाव में दोनो की भूमिका रही है। वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, स्वीडन द्वारा 2019 में प्रकाशित जर्मन राजनीति विज्ञानी अन्ना लुहरमैन के अध्ययन के अनुसार हर देश ने कहा है कि मुख्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर झूठ फैलाये गये और चीन और रूस सबसे ज्यादा झूठ फैलाने वाले देश थे। संभव नहीं कि चीन और रूस ऐसा करें और अमेरिका इससे वंचित हो। भारत पर विस्तृत अध्ययन नहीं आया, किंतु 2019 के चुनाव में ज्यादातर देशों ने स्वीकार किया कि झूठ और अफवाह फैला कर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। 2024 के चुनाव में हमने देखा कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा जैसे झूठ ने भूमिका अदा की। इसमें सोशल मीडिया, मुख्य मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी भूमिका थी। दलितों और जनजातियों के बीच लोगों का समूह जाकर का प्रचार करता था। इसलिए इन बातों की ठीक प्रकार से जांच हो। जांच रिपोर्ट में अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हों तो भले उन्हें सार्वजनिक न किया जाए किंतु भविष्य में ऐसी खतरनाक भूमिकाओं को रोकने के कदम उठाए जाने चाहिए।

रिश्तों में ना लाएं, मौसम जैसी तपिश

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया
लेखक स्तंभकार हैं।

आज के मौसम को जब हम शब्दों में बयान करना चाहे तो कलम भी भीग जाती है। लेकिन इसमें क्या सिर्फ मौसम की गलती है? यहाँ हम जब गर्मी की बात कर रहे हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी गर्मी से बचने के तरह-तरह के उपाय बता रहे हैं, जो शायद हम अपने लिए भी प्रयोग में लाते हैं। पर क्या मौसम की गर्मी से ही हमें बचने की जरूरत है? आजकल तो रिश्ते भी अहंकार, गुस्से और ईर्ष्या की तपिश में जलकर खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। जब हम मौसम की गर्मी से खुद को बचाने के लिए उपाय करते हैं, जिससे हम बीमार होने से बच सके तो फिर रिश्तों में आ रही तपिश से बचने के लिए हम सही समय पर सही कदम क्यों नहीं उठाते? हम क्यों अपने अनमोल रिश्तों को अपने अहम की तपिश में जलते हुए देखकर भी अनदेखा कर देते हैं?

रिश्तों में प्रेम की गर्माहट ही अच्छी लगती है, जलन की तपिश नहीं। और जब भी हमें एक भी पल ऐसा अनुभव हो की कोई अपना हमसे किसी छोटे से कारण से दूर हो रहा है तो जितनी जल्दी हो सके उस कारण को बातचीत के माध्यम से दूर करें। जिससे कि आपका अपनों के साथ रिश्ता अटूट बना रहे। बातचीत या फिर कुछ संदेश इशारे होते हैं जो दिलों को जोड़ते है। रिश्ता चाहे कोई भी हो प्यार से सींचा जाए तो वह सुंदर फूल की तरह खिलता है। बस हमें इशारों के साथ-साथ अपने व्यवहार को भी समझने की जरूरत है। कई बार शब्दों के शूल चलाते समय हम भूल जाते हैं कि ये वह अपने है, जिनके साथ हमने अच्छा समय भी बिताया है। यही है वो जो हमें अपनी यादों के सहारे हमारे जाने के बाद भी हमेशा ज़िंदा रखेंगे। इसलिए आज भी अपनों को प्रेम की अटूट डोरी से बांध लीजिए, जिससे कभी जलन या अहंकार की तपिश उन पर ना आने ना पाए।यकीन करें यह मुश्किल काम नहीं है। हमें अपने प्रेम से उनकी नाराजगी को दूर करना है। जिस तरह हर मौसम का अपना ही महत्व है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हर रिश्ते का महत्व है, और हर रिश्ते को निभाने की जिमेदारी हम सिर्फ घर के छोटो को नहीं दे सकते। जिस घर के बड़े अपनी जिमेदारियों को सही से नहीं निभाते ।उस घर के हर रिश्ते में शक और नफरत अपना घर बना लेती है। जिस प्रकार एक पेड़ को उसकी जड़े ही मजबूत बनाती है। ठीक उसी प्रकार एक घर को उसके बड़े-बजुर्ग ही अपनी सहनशीलता और समझदारी से रिश्तों की नीवं को मजबूत करने का काम करते ह। तो कुछ पल अपनों के साथ की ठंडी छाँव को ओढ़कर रिश्तों को नया रूप दें ।

पहल

न्यायमूर्ति रोहित आर्य
लेखक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति एवं भाजपा वन नेशन, वन इलेक्शन प्रदेश टोली के संयोजक है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' एक नई दिशा की ओर

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बार कहा था, कठिनाई नए विचारों को विकसित करने में नहीं, बल्कि पुराने विचारों से मुक्त होने में है।' संभवतः एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहे राजनीतिक दल और नेता पुराने विचारों से मुक्त होने में ही कठिनाई महसूस कर रहे हैं, या सिर्फ विरोध की राजनीति के तकाजे उन्हें इस अभिनव प्रयास का समर्थन करने से रोक रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी नीव विविधता में एकता की अवधारणा पर टिकी हुई है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' इसी विचारधारा को सशक्त बनाता है, जिससे संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जा सकें। यह विषय न केवल प्रशासनिक सुधार से जुड़ा है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र को अधिक संगठित, कुशल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक एतिहासिक कदम भी है। यह प्रणाली चुनावी प्रक्रिया को सरल बनायेगी, शासन को स्थिरता प्रदान करेगी और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले अनावश्यक बोझ को कम करेगी।

पहले भी होते रहे हैं एक साथ चुनाव-हालांकि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिशा में की गई पहल के बाद से चर्चा का विषय बना है, लेकिन यह कोई नया विचार नहीं है। भारत में 1952 के पहले आम चुनाव से ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराये जाते थे, इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते थे। उससे पहले यही प्रकिया ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी अपनाई गई थी। हालांकि, 1967 के बाद राजनैतिक और सामाजिक बदलावों के कारण यह व्यवस्था टूट गई। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद को भंग कर समय से पहले चुनाव कराए, जिसके बाद यह प्रवृत्ति और मजबूत हो गई। नतीजा यह हुआ कि आज हम वर्षभर में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग-अलग चुनाव होते हुए देखते हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव शासन व्यवस्था, आर्थिक संसाधनों और प्रशासनिक कार्यों पर पड़ा है। 1962 में भारतीय चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 'अगर संभव हो तो प्रयास और खर्च की पुनरावृत्ति से बचना चाहिये'। 1983 की वार्षिक रिपोर्ट में भी संसदीय और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की आवश्यकता को दोहराया गया। 170वीं विधि आयोग की रिपोर्ट ने तो इसे और आगे बढ़ाते हुये अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को इसका प्रमुख कारण बताया। इस अनुच्छेद का अत्यधिक प्रयोग भारत के संघीय ढांचे के लिये चिन्ता का विषय बना रहा है। 2015 में 79वीं स्थाई समिति की रिपोर्ट ने भी एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया।

दूषित हो गई लोकतांत्रिक प्रणाली-देश में होने वाले बहु-चरणीय चुनावों ने कई समस्याओं को जन्म दिया है और इनके कारण पैदा हुई बुराईयों ने हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही दूषित कर दिया है। चुनावों में बाहुबल का बढ़ता प्रयोग लोकतंत्र के लिये खतरा बन गया है। मतदान के दौरान होने वाली हिंसा जैसी घटनाएं चुनावी प्रक्रिया को बाधित करती हैं। बहु-चरणीय चुनावों में कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता है। चुनावों में फर्जी समाचार, सोशल मीडिया में दुष्प्रचार और मतदाताओं को गुमराह करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। बार-बार होने वाले चुनावों के कारण ध्यान शासन से हटकर चुनाव प्रचार पर चला जाता है, जिससे नीतियों के कियान्वयन में देरी होती है। इससे मुफ्तखोरी की राजनीति की शुरुआत हुई जो राज्य की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाती है। बार-बार होने वाले चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता विकास कार्यक्रमों और प्रशासन को बाधित करती है, जिससे नीतिगत गतिरोध उत्पन्न होता है और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है। हर बार के चुनावों में भारी सुरक्षा बल और कर्मचारियों की तैनाती होती है, जो न सिर्फ सरकारी संसाधनों पर दबाव डालती है, बल्कि आवश्यक सेवाओं को भी बाधित करती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में ही 70 लाख अधिकारियों की तैनाती हुई थी। बार-बार के चुनावों से मतदाताओं पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पडता है। वे उदासीनता और थकान महसूस करने लगते हैं। जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी सीमित हो जाती है।

देश के लिए हितकारी-केन्द्र सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' के विचार को आगे बढ़ाने के लिये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कोविन्द समिति का गठन किया था। इस समिति के सुझावों के आधार पर 129वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक साथ चुनाव होने से खर्च और प्रशासनिक लागत की बचत होगी। कम चुनाव निर्बाध शासन और नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। एक साथ होने वाले चुनाव केन्द्र और राज्य की नीतियों के बीच समन्वय में सुधार करेंगे। मतदान प्रतिशत बढेगा और एक साथ होने वाले चुनावों से राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास की राह प्रशस्त होगी, जो निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देगी। समिति ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का अनुमानित खर्च 1.35 लाख करोड बताया है। समिति के अनुसार एक देश, एक चुनाव से कम से कम 12000 करोड़ की बचत तो होगी ही, काले धन और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। समिति के अनुसार 'एक देश, एक चुनाव' देश के जीडीपी के 1.5 प्रतिशत की बचत कर सकता है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, अप्रत्याशित प्रचार खर्च कम होंगे और चुनाव के बाद मुद्रास्फीति में कमी होगी। यदि सभी चुनाव एक साथ कराए जाएँ, तो सरकार को पूरे पाँच साल तक निर्बाध रूप से कार्य करने का अवसर मिलेगा। इससे विकास की गति तेज होगी, सामाजिक योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा और जनता को वास्तविक लाभ मिलेगा।

सबका साथ, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया-कोविंद समिति ने एक देश, एक चुनाव के मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श किया। समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से इस प्रस्ताव पर सुझाव मांगे। इनमें से 47 दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिनमें से 32 दलों ने इसका समर्थन किया और 15 ने इसका विरोध किया। इसके अतिरिक्त, भारत के चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी अपनी राय दी और सभी ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं है। उच्च न्यायालयों के 9 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकी 3 ने असहमति व्यक्त की। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी समकालिक चुनावों के पक्ष में राय दी। इसके साथ ही समिति ने पूर्व राज्य चुनाव आयुक्तों, बार कॉंसिल, एसोचेम, फिक्की और सी.आई. आई. के अधिकारियों से भी चर्चा की। जनता से मांगे गए सुझावों में से 83 प्रतिशत प्रतिक्रियाएं (13,396) एक देश, एक चुनाव के पक्ष में थीं, जबकी केवल 17 प्रतिशत (2,276) ने इसका विरोध किया। इससे साफ है कि वर्तमान विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई थी। सार रूप में कहें तो 'एक राष्ट्र एक चुनाव' भारत के संविधान की मूल संरचना से प्रेरित है। इस देश के लोगों ने स्वयं ये संविधान अपनाया है, इस भावना से कि प्रत्येक नागरिक को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक न्याय सुलभ होगा। आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में तो केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने अतीत में कई कदम उठाए हैं, कई नीतियां बनाई हैं, परंतु राजनैतिक न्याय के क्षेत्र में प्रयास नगण्य ही रहे हैं। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार हालंकि नया नहीं है, परंतु इच्छा शक्ति के अभाव में इसके क्रियान्वयन के प्रयास नहीं किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों से इस सोच पर नए सिरे से विमर्श शुरू किया गया, ताकि धरातल पर इसका क्रियान्वयन संभव हो सके। यह कदम संविधान की अधोसंरचना के अनुरूप है, क्योंकि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' जनता को राजनैतिक न्याय दिलाने की दिशा में एक साहसिक एवं अहम पहल है, जो कि देश के नागरिकों के संदर्भ में निश्चित रूप से सार्थक भी है।

जॉन एफ. कैनेडी ने कहा था, 'छत की मरम्मत का सही समय तब होता है जब धूप खिली हो'। अब समय आ गया है कि समाज के विकास और सुशासन के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार को अपनाया जाए। जो 'जो अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक एतिहासिक कदम होगा। 'एक राष्ट्र एक चुनाव' केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र को अधिक संगठित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा 'एकता के अपने प्रयासों के तहत, हम अब एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करेगा और 'विकसित भारत' के सपने को नई प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। आइए, हम सब इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें और भारत को एक अधिक संगठित, शक्तिशाली और समृद्ध लोकतंत्र बनाने में अपना योगदान दें।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

उज्जैन विक्रमोत्सव पर विशेष

राजशेखर व्यास

लेखक पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो हैं।

यूं शुरू हुआ था विक्रम महोत्सव, विक्रम भारत का सोया हुआ पराक्रम था

सारे देश में उनकी इस योजना का सम्यक स्वागत हुआ उन्हें सबसे पहले कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी से सहयोग मिला, महाराजा देवास ने योजना सुन कर कहा सारे सूत्र उनके हाथ में रहें तो वे सहयोग देंगे तब तक वीर साँवरकर ने भी अपने पत्र में इस योजना की प्रशंसा कर दी चूँकि पंडित सूर्यनारायण व्यास आज़ादी के पहले 114 स्टेट के राज्य ज्योतिषी भी थे उनकी इस योजना का सारे देश में सम्यक स्वागत हुआ और महाराजा ग्वालियर ने उन्हें ग्वालियर बुला भेजा। चार दिन घंटों-घंटों विचार विमर्श हुआ और अंत में व्यास जी के सुझाव पर उज्जयिनी से ले कर मुंबई तक विक्रम महोत्सव मनाना स्वीकार हुआ । व्यास जी विक्रम के नाम पर एक विश्वविद्यालय, शहर में एक भी भव्य सभागार नहीं था पहले भी पृथ्वीराज कपूर आये थे तो महाराजवाड़ा, रीगल टाकीज, कैलाश टाकीज में पैसा पठान दीवार नाटक खेल समारोह के लिए चन्दा एकत्र किया गया था तो विक्रम के नाम पर एक भव्य सभागार ' विक्रम कीर्ति मंदिर' बनाने का विचार किया ।

भारत गुलाम था और हमें इतिहास में पढ़ाया जा रहा था कि हम सदियों से गुलाम रहें हैं,कभी शक और हुन् के,कभी मुग़ल और कभी अंग्रेजों के हम सदियों से लूटे पिटे हारे थके जूँवारी हैं। पाँच सौ साल हम पर मुग़लों ने शासन किया और दो सौ साल से अंग्रेज़ हम पर शासन करते आ रहें थे। यह बात है 1940 के आसपास की उज्जयिनी के क्रांतिकारी युवा सूर्यनारायण व्यास ने, जिनका प्रचलित संवत् भी धीरे-धीरे लोग भूलते जा रहें थे। इतिहास से ऐसे पराक्रमी चरित्र 'विक्रम' के नाम पर उज्जयिनी से एक मासिक पत्रिका 'विक्रम' का प्रकाशन आरम्भ किया चूँकि उनका अपना प्रिंटिंग प्रेस था जहाँ से वे अपने पूज्य पिता महा महोपाध्याय पंडित नारायण व्यास जी के नाम पर 'नारायण विजय पंचांग' अपने छोटे भाई के साथ प्रकाशित करते ही थे! पर विक्रम संवत् के दो हज़ार वर्ष पूर्ण होने जा रहे थे और विक्रमादित्य के नाम पर राष्ट्र में कोई हलचल नहीं थी उन्होंने विक्रम संवत् के दो हज़ार वर्ष पूर्ण होने पर 'विक्रम द्वि सहस्त्राब्दी महोत्सव' की योजना बनायी और पृथ्वीराज कपूर को ले कर सारे राष्ट्र में जागृति फैलाने 'विक्रमादित्य' फ़िल्म का निर्माण शुरू कर दिया।

सारे देश में उनकी इस योजना का सम्यक स्वागत हुआ उन्हें सबसे पहले कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी से सहयोग मिला, महाराजा देवास ने योजना सुन कर कहा सारे सूत्र उनके हाथ में रहें तो वे सहयोग देंगे तब तक वीर साँवरकर ने भी अपने पत्र में इस योजना की प्रशंसा कर दी चूँकि पंडित सूर्यनारायण व्यास आज़ादी के पहले 114 स्टेट के राज्य ज्योतिषी भी थे उनकी इस योजना का सारे देश में सम्यक स्वागत हुआ और महाराजा ग्वालियर ने उन्हें ग्वालियर बुला भेजा। चार दिन घंटों-घंटों विचार विमर्श हुआ और अंत में व्यास जी के सुझाव पर उज्जयिनी से ले कर मुंबई तक विक्रम महोत्सव मनाना स्वीकार हुआ । व्यास जी विक्रम के नाम पर एक विश्विद्यालय, शहर में एक भी भव्य सभागार नहीं था पहले भी पृथ्वीराज कपूर आये थे तो महाराजवाड़ा, रीगल टाकीज, कैलाश टाकीज में पैसा पठान दीवार नाटक खेल समारोह के लिए चन्दा एकत्र किया गया था तो विक्रम के नाम पर एक भव्य सभागार 'विक्रम कीर्ति मंदिर' बनाने का विचार किया ।

थे। मैथिली शरण गुप्त ने अपने हस्त लेख में - दो हज़ार संवत्सर बीते हैं / निज विक्रम बिना हम मरे मरे जीते हैं / नित्य नये शक और हूँन हमारे जीवन रस पीते हैं, होकर भी हुए क्या हम उनके मन चीते हैं? भविष्य दृष्टा व्यास जी जानते थे दस साल के अंदर हम स्वतंत्र तो हो जायेंगे पर स्वतृंतता उपरांत भी मानसिक गुलामी और सांस्कृतिक दासता से मुक्त नहीं हो पायेंगे । प्रखर पत्रकार क्रांतिकारी पंडित व्यास ने वर्ष 1942 में उज्जैन से 'विक्रम' मासिक आरम्भ किया और उसके माध्यम से सारे राष्ट्र के सोये पराक्रम को जगाने का उपक्रम किया विक्रम संवत् के दो हज़ार वर्ष पूर्ण होने पर 114 राजा महाराजा इकट्ठा कर विक्रम महोत्सव मनाना आरंभ किया आज उज्जयिनी में स्थापित विक्रम विश्वविद्यालय विक्रम कीर्ति मंदिर उनके इसी महान अवदान की कीर्ति गाथा हैं

विक्रम की प्रमाणिकता ऐतिहासिकता पर पंडित सूर्यनारायण व्यास निरंतर लिख कर अंग्रेज़ इतिहासकारों को मुंहतोड़ उत्तर दे ही रहे थे, विक्रम कीर्ति मंदिर स्थापित कर उन्होंने महाकाल मंदिर में उज्जयिनी की पहली खुदाई से प्राप्त पुरातत्व प्रमाण रखवाये थे वे अपने ही काल में खुद के द्वारा स्थापित सिंधिया शोध प्रतिष्ठान विगत वर्षों में महाकाल में रखवायी सारी प्रतिमाओं का संग्रहालय बना दिया, बाद के काल में उनके सुयोग्य शिष्य डॉ विष्णु श्री धर वाकनकर ने विक्रम के काल की सोने की मुद्रा खोज कर उनकी शोध को प्रमाणिकता ही दी। अब उनका लक्ष्य विक्रम को जन जन तक पहुचाना था तो उन्होंने पृथ्वी राज कपूर को प्रेम अदीब रत्न माला बाबूराव पेंढ़ारकर को ले कर 'विक्रमादित्य' विजय भट्ट के निर्देशन में बनायी । इस फ़िल्म ने रजत जयंती मनायी। आज की नई पीढ़ी तो संभवतः कल्पना भी नहीं कर सकती की कैसे सारी उज्जयिनी नगरी दुल्हन की तरह सज धज गई थी अपने निज विक्रम के स्वागत के लिये सारा नगर रंग बिरंगी पताकाओ से सज गया जिस पर पराक्रमी विक्रम का चित्र था, वही चित्र जो बाद के काल में विक्रम का मुख पृष्ठ और संपादकीय पृष्ठ का चित्र बनता सजता सँवरता रहा। सारे देश में घूम-घूम कर

महान विद्वान लोगो से विक्रम, कालिदास, उज्जयिनी पर शोध लेख लिखवाये गये जिनमे महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, डॉ. भगवत शरण उपध्याय वि वा मीराशी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डी सी मजूमदार जैसे असंख्य महान नाम हैं हृदय हमारे/हाथ हमारे रिते हैं, जो विक्रम स्मृति ग्रंथ में व्यास जी ने सबसे आगे प्रकाशित की। यूँ व्यास जी के अनुरोध पर इस से पूर्व कविवर रवींद्रनाथ टेगोर उज्जयिनी कविता लिख चुके थे और उज्जयिनी भारती भवन रहते हुए नागार्जुन - कालिदास सच सच बतलाना, अज रोया था या तुम रोये थे लिख चुके थे।

विक्रम स्मृति ग्रंथ कैसे तैयार हुआ उसके बारे में डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन एक दिलचस्प क़िस्सा सुनाते थे उन दिनों वे ग्वालियर में क्रींस विक्टोरिया कालेज में थे और महापंडित राहुल जी आये हुए थे। चालीस बरस के सूर्यनारायण व्यास विक्रमादित्य फ़िल्म के सेट से दिल्ली आये और दिल्ली से सड़क मार्ग से ग्वालियर आ कर राहुल जी को पकड़ा -विक्रम पर आपका लेख लिये बग़ैर नहीं जाऊँगा ! डॉ सुमन बड़े गर्व से और चाव से बताते थे -राहुल जी हमारी हॉस्टल के बरामदे में ईक गमझा मुँह पर ओढ़ कर बैठ गये - मैं बोलता हूँ सुमन लिखेगा और आज आप विक्रम पर मेरा लेख ले कर ही जाएँगे व्यास जी! डॉ सुमन बताते थे वे दो घंटे आँख पर गमछा डाले बोलते रहें मैं लिखता रहा और यूँ - त्रिविक्रम! लेख तैयार हुआ, सुमन जी बताते थे कैसे व्यास जी सारा खाना पीना छोड़ कर दीवाने की तरह विक्रम महोत्सव और कालिदास समारोह के लिये सारे देश में दौड़ते फिरते थे।

विक्रमादित्य फ़िल्म में काम करने के बदले पृथ्वी राज कपूर ने व्यास जी की मित्रता वश कोई पारिश्रमिक नहीं लिया था, व्यास जी उनका यह कर्ज उतारा जब प्रथम राष्ट्रपति ने पंडित सूर्य नारायण व्यास को 'पद्मभूषण' साहित्य शिक्षा संस्कृति में योगदान के लिये प्रदान किया तो वे चाहते थे व्यास जी राज्य सभा में भी आये वाहन बालकृष्ण शर्मा नवीन मैथिली शरण गुप्त पहले ही मौजूद थे, व्यास जी ने इस अनुरोध को यह कह कर बाबू से प्रथ्वी राज कपूर के लिए मौड़ दिया की बाबू! कला जगत से अब तक आपने किसी को राज्य सभा में सम्मान दिया नहीं हैं और इस तरह पृथ्वीराज कपूर राज्य सभा में ससम्मान विराजमान हुए।

इस भव्य आयोजन से जुड़े कुछ दर्दनाक मर्मनाक पहलू भी हैं मसलन लॉर्ड वेवल जिन्ना के विरोध के कारण राजा महाराजों ने आयोजन से हाथ खेंच लिए जिन्ना ने साँवरकर के आयोजन की प्रशंसा से चिढ़ कर इसे हिंदू आयोजन बता कर विरोध किया जबकि विक्रमादित्य भारत के सोए पराक्रम को जगाने का नाम था, लॉर्ड वेवल ने इसे अंग्रेज़ विरोधी मानकर महाराजा सिंधिया से विरोध जताया। तब घनश्याम दास बिरला द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय के लिए भेजे दस लाख रुपये जो उज्जयिनी के आयोजन के लिए ईयर मार्क थे उससे ग्वालियर में मेडिकल कालेज बना लिया गया इतना ही नहीं ग्वालियर से ज़्यादा पैसा मालवा का था सर सेठ हुकुमचंद द्वारा व्यास जी के। अनुरोध पर फिर एक बड़ी रकम दी गई जिस से विक्रम विश्वविद्यालय बना पर इस अचानक आए विरोध और अवरोध से पूर्व विक्रम विश्व विद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर, विक्रम स्मृति ग्रंथ का काम तो हो गया था, मगर विक्रम स्मृति स्तम्भ का काम रह गया जो आज तक बना नहीं। उम्मीद ही नहीं विश्वास हैं प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जैसे उज्जयिनी का मेडिकल कालेज ले आए 'विक्रम समृति स्तंभ' भी एक दिन बना ही देंगे।

कवि कालिदास फ़िल्म तो आज भी यू ट्यूब पर उपलब्ध हैं जिसमे पंडित सूर्यनारायण व्यास के महान योगदान का भारत भूषण के स्वर में उल्लेख किया गया हैं बाद के काल में पद्म भूषण पंडित व्यास के प्रयास से डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इस फ़िल्म को सारे देश में टेक्स फ्री कर दिया था। नई पीढ़ी संवत् 2000 में मनाए इस भव्य तम विक्रम महोत्सव का इतिहास जाने और जाने की आज उसकी स्मृति में खड़े विक्रम विश्विद्यालय विक्रम कीर्ति मंदिर और संसार का महान ग्रंथ उपलब्ध हैं - विक्रम स्मृति ग्रंथ।

आज जन्मदिन

ओ.पी.शर्मा

(लेखक दिग्विजय सिंह के निज सचिव हैं)

दिग्विजय सिंह : व्यक्तित्व और कृतित्व

फरवरी का महीना बसंत ऋतु का प्रतीक है–उत्साह, उमंग, प्रेम और कर्तव्यपरायणता से भरा हुआ। संत रविदास जी, महाशिवरात्रि, नर्मदा जयंती, छत्रपति शिवाजी जयंती, एकलव्य जयंती जैसी महत्वपूर्ण तिथियाँ इस महीने की गरिमा को और बढ़ा देती हैं। इन सभी में एक विशेष दिन और भी जुड़ा हुआ है–28 फरवरी, जब मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का जन्म हुआ था।

दिग्विजय सिंह ने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जिन मूल्यों को आत्मसात किया है, वे इन्हीं पर्वों के प्रतीकात्मक संदेशों से मेल खाते हैं। उनके जीवन में कर्तव्यपरायणता, समता, सामाजिक समरसता, भक्ति, त्याग और साहस का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है।

नर्मदा परिक्रमा: आध्यात्मिकता और समर्पण का प्रतीक: दिग्विजय सिंह ने नर्मदा की 3,000 किलोमीटर लंबी पैदल परिक्रमा कर यह साबित किया कि धर्म उनके लिए केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाली शक्ति है। उन्होंने यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभूति के लिए की, बल्कि समाज के हर वर्ग से जुड़कर उनकी पीड़ा को समझने और समाधान तलाशने के उद्देश्य से भी की। इस यात्रा में उन्होंने ग्रामीणों, आदिवासियों, संतों और विद्वानों के साथ समय बिताया और उनकी जीवनशैली को नजदीक से देखा।

शिवत्व और संघर्ष का मार्ग: महाशिवरात्रि के पावन पर्व की तरह, दिग्विजय सिंह का जीवन भी विषपान करने और समाज को सुगंधित फूलों की तरह महकाने का एक प्रयास रहा है। राजनेता होने के नाते उन्होंने आलोचनाओं, आरोपों और अपमान के विष को पीकर भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित हुए बिना जनसेवा का मार्ग अपनाया। ठीक वैसे ही जैसे शिव विष को अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ कहलाए।

गुरुभक्ति और एकलव्य की निष्ठा: दिग्विजय सिंह की श्रद्धा अपने गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रति ठीक वैसे ही रही जैसे एकलव्य की गुरु द्रोणाचार्य के प्रति। उन्होंने अपने गुरु के विचारों और मार्गदर्शन को आत्मसात कर अपने राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित किया। उनके व्यक्तित्व में विनम्रता और दृढ़ संकल्प, दोनों ही दिखाई देते हैं।

छत्रपति शिवाजी की विरासत: छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह, दिग्विजय सिंह भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने राजनीति में रहते हुए सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर होने के कारण वे सदैव जनता की आवाज बने हुए है।

सर्वधर्म समभाव का संदेश: दिग्विजय सिंह का दृष्टिकोण सदा सर्वधर्म समभाव का रहा है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया। वे इस बात में विश्वास रखते हैं कि राम, कृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद–सभी मानवता के कल्याण के लिए आए। उनकी यही सोच उन्हें एक सच्चे धर्मनिष्ठ और प्रगतिशील नेता के रूप में स्थापित करती है।

पिछले 23 वर्षों में दिग्विजय सिंह जी के साथ काम करते हुए उन्हें बहुत करीब से देखने का अवसर मिला और मैंने पाया कि वे केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक विचारशील, संवेदनशील और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विशेष

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का संकल्प

बच्चों को विज्ञान को बतौर कैरियर चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि देश की आने वाली पीढ़ी विज्ञान के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे सके और देश प्रगति के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर रहे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित करने के लिए वर्ष 1986 में भारत सरकार को कहा गया था और सरकार द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद से 28 फरवरी 1987 से प्रतिवर्ष इसी दिन भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक महान कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता रहा है। यह दिवस भारत के महान् वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री सर सी. वी. रमन की खोज 'रमन प्रभाव' को सदैव याद रखने और विश्व पटल पर विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने वाले इस वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए उनकी स्मृति में मनाया जाता है। दरअसल सर सी वी रमन भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में पहले ऐसे भारतीय थे, जिन्होंने भारत में ऐसे आविष्कार पर शोध किया था।

मानव जीवन को विज्ञान ने आज बेहद आसान और सुविधाजनक बना दिया है। युवाओं की विज्ञान के प्रति आज के समय में कितनी रूचि है, इसी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। युवाओं के साथ-साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के दिलोदिमाग में विज्ञान के प्रति अधिकाधिक रूचि जागृत करने के लिए ही प्रतिवर्ष 28 फरवरी को 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' मनाया जाता है। दरअसल इस दिवस के जरिये बच्चों को विज्ञान को बतौर कैरियर चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि देश की आने वाली पीढ़ी विज्ञान के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे सके और देश प्रगति के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर रहे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित करने के लिए वर्ष 1986 में भारत सरकार को कहा गया था और सरकार द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद से 28 फरवरी 1987 से प्रतिवर्ष इसी दिन भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक महान कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता रहा है। यह दिवस भारत के महान् वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री सर सी. वी. रमन की खोज 'रमन प्रभाव' को सदैव याद रखने और विश्व पटल पर विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने वाले इस वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए उनकी स्मृति में मनाया जाता है। दरअसल सर सी वी रमन भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में पहले ऐसे भारतीय थे, जिन्होंने भारत में ऐसे आविष्कार पर शोध किया था।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में 1907 से 1933 तक सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन ने कार्य किया था। उस दौरान उन्होंने भौतिकी के कई बिन्दुओं पर शोध किया था, जिसमें से 'रमन प्रभाव' (प्रकाश के फैलने पर प्रभाव, जब विभिन्न वस्तुओं के द्वारा उसे गुजारा जाता है) उनकी महान सफलता और खोज बनी, जो न केवल विज्ञान जगत में लोकप्रिय हुआ बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी इस खोज को सराहा। सर सी वी रमन की यह खोज 28 फरवरी 1928 को दुनिया के सामने आई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनकी इस खोज ने तहलका मचा दिया था। उनके इसी बड़े आविष्कार के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला 'नोबेल पुरस्कार' दिया गया था। वे एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव हासिल हुआ था। 'रमन प्रभाव' खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार के अलावा भी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात् भारत लौटने पर उन्होंने कहा था कि मेरे जैसे न जाने कितने ही रमन सुविधाओं और अवसरों के अभाव में यूं ही अपनी प्रतिभा गंवा देते हैं, जिससे केवल उनका ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नुकसान है, जिसे हमें रोकना होगा।'' वर्ष 2013 से अमेरिकन केमिकल सोसायटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक केमिकल लैंडमार्क के रूप में 'रमन प्रभाव' को नामित किया गया।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष एक निर्धारित थीम के तहत मनाया जाता है। 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है 'विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना'। 2024 में यह दिवस 'विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक' और 2023 में 'वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान' थीम के साथ मनाया गया था। वर्ष 2022 की थीम थी 'सतत भविष्य के लिए विज्ञान और

प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण' और वर्ष 2021 की थीम थी 'एसटीआई का भविष्य : शिक्षा कौशल और कार्य का प्रभाव'। एसटीअई का अर्थ है साइंस, टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यह विषय शिक्षा कौशल और कार्य पर विज्ञान, प्रोद्यौगिकी और नवाचार (एसटीअई) के भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की वर्ष 1999 से लेकर अब तक की थीम पर नजर डालें तो वर्ष 1999 का विषय था 'हमारी बदलती धरती'। वर्ष 2000 का विषय था 'मूल विज्ञान में रूचि उत्पन्न करना, 2001 का 'विज्ञान शिक्षा के लिए सूचना तकनीक', 2002 का 'पश्चिम से धन', 2003 का 'जीवन की रूपरेखा : 50 साल का डीएनए और 25 वर्ष का आईवीएफ', 2004 का 'समुदाय में वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देना', 2005 का 'भौतिकी को मानना', 2006 का 'हमारे भविष्य के लिए प्रकृति की परवरिश करें', 2007 का 'प्रति द्रव्य पर ज्यादा फसल', 2008 का 'पृथ्वी ग्रह को समझना', 2009 का 'विज्ञान की सीमा को बढ़ाना', 2010 का 'दीर्घकालिक विकास के लिए लैंगिक समानता, विज्ञान और तकनीक, 2011 का 'दैनिक जीवन में रसायन', 2012 का 'स्वच्छ ऊर्जा विकल्प और परमाणु सुरक्षा', 2013 का 'अनुवांशिक संशोधित फसल और खाद्य सुरक्षा', 2014 का 'वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करना', 2015 का 'राष्ट्र निर्माण के लिए विज्ञान', 2016 का 'देश के विकास के लिए वैज्ञानिक मुद्दों पर सार्वजनिक प्रशंसा बढ़ाने के लक्ष्य', 2017 का 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकलांग व्यक्तियों के लिए', 2018 का 'एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी' तथा वर्ष 2019 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय 'लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग' था। देश में अन्य क्षेत्रों के अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं के योगदान के मद्देनजर उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम रखी गई 'विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं' (वूमेन इन साइंस)। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों की महत्ता से परिचित कराना होता है, इसके अलावा वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों को अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें उनके कार्य के लिए प्रोत्साहित करना भी इसका अहम उद्देश्य है। विज्ञान के विकास के लिए नई तकनीकों को लागू कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने जैसे उद्देश्य राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के आयोजन में निहित हैं। विज्ञान के जरिये ही वैज्ञानिकों ने नई-नई तरह की तकनीकों का आविष्कार किया है और वैज्ञानिकों ने इन खोजों के जरिये मानव जीवन को बहुत बेहतर बना दिया है। इसी विज्ञान के जरिये हम रोबोट, कम्प्यूटर इत्यादि बनाने में सफलता प्राप्त करने के अलावा अंतरिक्ष तक में पहुंच गए हैं और असंभव दिखने वाले कार्यों को भी विज्ञान की मदद से ही संभव बनाते रहे हैं। विज्ञान की मदद से ही बनाई गई प्रतिदिन बहुत सारी तकनीकों और वस्तुओं का इस्तेमाल हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में करते भी हैं। ऐसे में हम सभी के लिए हमारे जीवन में विज्ञान के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। हमारा समाज 21वीं सदी में जिस प्रकार अंधविश्वासों के साये में जीता है, ऐसे में विज्ञान की महत्ता समझते हुए समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हुए इन अंधविश्वासों के निर्मूलन की जिम्मेदार हम सबकी है।

शासन के आदेश की अवहेलना कर शिक्षिका को किया अटैच

एक शिक्षक के भरोसे प्राथमिक शाला खोदरी, नए बीईओ के पदभार संभालते ही शाहपुर में अटैचमेंट का खेल शुरू

बैतूल / भौंरा। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में शिक्षकों की कमी के चलते जंहा गांवों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता है, और अन्य समस्याओं का सामना करना पता, वहीं शिक्षा विभाग के कर्ताधर्ता लम्बे अर्से से अटैचमेंट पर रोक होने के बावजूद अभी भी इसे जारी रखे है। ताजा मामला शाहपुर ब्लॉक मुख्यालय से करीब 4 किमी दूर ग्राम पंचायत कुंडी के ग्राम खोदरी का है, जहां पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक में कुल 18 बच्चे दर्ज हैं और यहां बच्चों की पढ़ाई हेतु एकमात्र शिक्षक है। पदस्थ शिक्षक को कभी किसी काम के लिए जब बाहर जाना पड़ता है तो बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस स्कूल में एक महिला शिक्षक की पोस्टिंग हुई थी, जिसे कुंडी स्कूल में अटैच कर दिया गया है। ग्राम के बसंत भलाबी सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय की समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों को मौखिक अवगत कराया गया एवं बीआरसी कार्यालय में पालक शिक्षक संघ एवं ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया, बावजूद इसके व्यवस्था जस की तस ही है और तो और हमारे ज्ञापन की ओसी पर रिसीविंग तक नहीं दी गई। यहां उल्लेखनीय है कि बीआरसी, बीईओ एवं कुंडी हाईस्कूल के प्राचार्य का पद, तीनों ही पद, गुलाबराव बर्डे के पास ही है। इसको लेकर भी किसी उच्चाधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। शिक्षक को शासकीय कार्य से बाहर जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने एक शिक्षक की अविलंब व्यवस्था करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक शाला खोदरी में पदस्थ शिक्षिका गीता उईके को बीआरसी गुलाबराव बर्डे के कहने पर कुंडी स्कूल में अटैचमेंट किया गया है, क्योंकि मेडम कुंडी की रहने वाली है। इस कारण बीआरसी ने उन्हें कुंडी स्कूल में पदस्थ किया है, जबकि कुंडी स्कूल के प्राचार्य के पास बीआरसी का प्रभार भी है। जानकार बताते है कि मूल पद शासन द्वारा आदेशित होते हैं। मूल पद को किसी और को प्रभार पर नहीं दिया जा सकता, जब तक कि मूल पद के कर्मचारी या अधिकारी के साथ कोई आकस्मिक स्थिति नहीं बनतीं। श्री बरडे द्वारा कुंडी प्राचार्य का मूल पद किसी और को स्वयं कैसे प्रभार में सौंपा, यह विचारणीय बात है।

एक ही शिक्षक के पास है यह सब पद/ प्रभार

1. मूल पद प्राचार्य हाई स्कूल कुंडी,
2. बीआरसी का पद प्रभार में,
3. कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र. 7328 के अनुसार स्थानीय व्यवस्था हेतु बीईओ के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
4. शास. उत्कृष्ट उच्चतर माध्य. विद्यालय शाहपुर का वित्तीय प्रभार (डीडीओ का चार्ज भी) जबकि कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र-2084 दिनांक 20-05-24 के आधार पर एकलव्य स्कूल के साथ-साथ इनके द्वारा शास. उत्कृष्ट उच्च. मा. विद्यालय शाहपुर का वित्तीय प्रभार भी ले लिया, जबकि इस पत्र में सिर्फ एकलव्य स्कूल के प्रभार का उल्लेख था।

इनका कहना है -

हाईस्कूल कुंडी के पद पर मेरी पदस्थापना है। उसके बाद मुझे बीआरसी का चार्ज दिया गया। नामदेव सर के बीईओ पद से रिटायर होने पर तात्कालिक व्यवस्था के रूप में यह पद भी मुझे दे दिया। मेरे द्वारा डीपीसी को 17 फरवरी को पत्र दिया कि दो ब्लॉक स्तर के पद पर कार्य करने से मैं अपने कार्य को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा हूं। अतः मुझे बीआरसी के पद से हटा दिया जाए। इसके अलावा मैंने हाईस्कूल कुंडी के पद पर प्रभारी प्राचार्य को चार्ज दे दिया है, चूंकि मैं सीनियर प्राचार्य के पद पर लंबे अर्से रहा हूं, इसलिए बीईओ का पद मेरे लिए उपयुक्त है।

- गुलाबराव बर्डे, बीआरसी शाहपुर

तात्कालिक व्यवस्था के रूप में उन्हें बीईओ का प्रभार दिया गया, शीघ्र ही वहां बीईओ और बीआरसी की नियुक्ति की जायेगी। और रही बात अटैचमेंट की, तो अटैचमेंट शासन स्तर से बंद है। यदि अटैचमेंट किया गया है तो जांच करवाकर तत्काल हटवाया जायेगा।

-शिल्पा जैन,
सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग बैतूल

आपके माध्यम से मुझे इस मामले की जानकारी लगी है। मैं इस मामले में शीघ्र ही जांच करवाता हूं।

- बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी।

भाजपा के शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, साजिश के तहत भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। एक अधिकारी को तीन-तीन प्रभार देकर भाजपा शासन काल में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। कांग्रेस जल्दी रणनीति बनाकर इसका जिला स्तर पर विरोध करेगी।

- राहुल उईके,
पूर्व विधायक प्रत्याशी, घोड़ाडोंगरी विधानसभा

श्री संत सांडल्य जी महाराज भोपाल की करनपुर में की गई अगवानी, किया पौधारोपण

सुबह सवेरे सोहागपुर। मां नर्मदा जी के तटीय क्षेत्र की पैदल आध्यात्मिक ज्ञान को बढाने धर्म के प्रचार के लिए आस्था के साथ पैदल परिक्रमावासियों के साथ संत सांडल्य जी महराज इसके करनपुर आगमन पर जन अभियान परिषद सोहागपुर टीम के सहयोग से

अगवानी करके स्वागत किया गया।इस अवसर पर संत श्री संत सांडल्य जी महाराज भोपाल वालो का करनपुर एवं सोहागपुर आगमन पर जन अभियान परिषद,नवांकुर,मेंटरो , छात्रों एवं समाजसेवीयों की टीम ने करनपुर में चेनसिंह कुशवाहा के निज निवास पर रोड के किनारे पौधारोपण किया गया।इसी अवसर पर जन अभियान परिषद सोहागपुर की टीम एवं चैन सिंह कुशवाहा करनपुर ने सेवा भाव से स्वल्पाहार आदि की व्यवस्था करने का अवसर प्राप्त किया। इस अवसर पर सोहागपुर जन अभियान परिषद् से किशोर कड़ोले, समाजसेवी विशाल गोलानी, नवांकुर,मेंटरो से गजेंद्र ठाकुर सचिन विश्वकर्मा, नेहा चौरसिया, संदेश मिश्रा, चेनसिंह, लता कुशवाहा, रानू मेहरा, छात्रा लता कुशवाहा आदि उपस्थित थे।

विश्व कल्याण ,सर्व रोग निवारणार्थ ,सुख शांति समृद्धि के लिए शंभू दरबार में विशेष पूजन-अर्चन

सुबह सवेरे सोहागपुर। शिवरात्रि के पावन महापर्व पर इस वर्ष भी ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव पंडित मनमोहन मुदगल जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं आध्यात्मिक गुरु पंडित प्रकाश मनमोहन मुदगल के पावन सानिध्य में रुद्र अभिषेक रुद्री निर्माण शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम किया गया। जिसमें विश्व कल्याण , सर्व रोग निवारणार्थ सुख शांति समृद्धि के लिए महामृत्युंजय मृत्युंजय अभिषेक किया गया । इस अभिषेक कार्यक्रम में ब्राह्मण विध्वंजन आचार्य स्वदेश दुबे शास्त्री

जी बरेली ,पंडित गौरी शंकर जी शास्त्री पिपरिया ,पंडित शैलेंद्र शास्त्री सोहागपुर आदि के द्वारा मंत्रोच्चार से अभिषेक संपन्न हुआ ।इस कार्यक्रम में अन्य नगरों से महाराज जी के शिष्य ,परिवार सहित शामिल हुए। वहीं स्थानीय नागरिक एवं श्रद्धालुओं की उपस्थिति भी भारी संख्या में रही ।इस अवसर पर गृहस्थ साधक आध्यात्मिक गुरु पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल ने अपने उद्बोधन में महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी को अपने इष्ट की प्रधानता एवं भगवान भोलेनाथ की भक्ति के विषय में अवगत कराया । वहीं आपने आगे कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व निशि थी ।एक अलौकिक दिव्य रात्रि हम सबके बीच आती है। जिसमें हम अपनी साधनाओं के द्वारा अपने दहिक, दैविक ,भौतिक तीनों प्रताप के संस्थापकों की निवृत्ति के लिए हम अभिषेक रुद्री का निर्माण एवं भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अभिषेक करते हैं। आपने आव्काहान किया कि शिवरात्रि पर्व सभी सनातन धर्मावलंबियों को मनाना चाहिए । इसी अवसर पर श्री शंभू दरबार में भंडारे का आयोजन किया गया था। जिसमें श्रद्धालु भक्त जनों ने प्रसादी ग्रहण की।

भोपाली मेले में मांझी सरकार के सैनिक ने रंगे हाथों पकड़ा बाइक चोर

ईमानदारी की मिसाल पेश की, महिला को गुम हुए 10 हजार रुपए लौटाए

बैतूल। भोपाली मेले में इस बार भी मांझी सरकार के सैनिकों ने अपनी निष्ठा और ईमानदारी से सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। जानकारी के अनुसार, मेले में उत्तर प्रदेश के चोर गिरोह सक्रिय थे, जो चोरी की वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी दौरान मांझी सरकार के

सैनिक अशोक वरकडे ने एक बाइक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके अलावा, मांझी सरकार के सैनिक बलिराम उइके ने मेले में एक महिला के गुम हुए 10 हजार रुपए की राशि उन्हें लौटा दी। इस सराहनीय कार्य के लिए एडिशनल एसपी ने मांझी सरकार के सैनिकों की प्रशंसा की और पुलिस प्रशासन ने भी उनका आभार जताया।

महाशिवरात्रि के अवसर पर हर साल आयोजित होने वाले भोपाली मेले में मांझी सरकार के सैनिक निःस्वार्थ रूप से तीन दिन तक सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं। इस बार भी उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी सेवाएं दीं। थाना प्रभारी रानीपुर तिवारी ने मांझी सरकार की पूरी टीम का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। दिल्ली प्रतिनिधि श्रवण कुमार परते और जिला मंत्री रामकिशोर धुर्वे ने बताया कि उनकी आदिवासी किसान सैनिक संस्था के सैनिक हर साल निःशुल्क सुरक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह सेवा कार्य समाज के प्रति उनकी निष्ठा और संस्कारों का प्रतीक है।

कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रारंभ, 20 हजार 223 विद्यार्थियों ने हिंदी विषय का दिया प्रश्न पत्र

हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के अंग्रेजी विषय की परीक्षा आज

बैतूल। जिले में हाई स्कूल कक्षा 10वीं की परीक्षा गुरुवार से प्रारंभ हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.अनिल सिंह कुशवाह ने बताया कि जिले के 126 परीक्षा केंद्रों पर 20 हजार 223 विद्यार्थियों ने हिंदी विषय का प्रश्न पत्र हल किया। जिला स्तर पर गठित उडन् दस्ता द्वारा परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान नकल के प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज 28 फरवरी 2025 को हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 12वीं अंतर्गत अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र आयोजित होगा। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.अनिल सिंह कुशवाह ने बताया कि कक्षा दसवीं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में कुल 20 हजार 921 परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना था, जिसमें 698 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे एवं 20 हजार 223 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। नकल प्रकरणों को रोकने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर जिले में विभिन्न स्तरों पर बनाए गए उडन् दस्तों द्वारा परीक्षा केंद्रों का सतत निरीक्षण किया गया। विभिन्न स्तर पर बनाए गए उडन् दस्तों द्वारा समाचार जारी किए जाने तक, प्रश्न पत्र के दौरान 65 केंद्रों का निरीक्षण किया गया। विभिन्न केंद्रों पर नकल संबंधी कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ।

मोबाइल एप से हो रही परीक्षा की निगरानी- जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. कुशवाहा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संपूर्ण परीक्षा पर निगरानी रखे जाने की दृष्टि से मोबाइल एप विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्तरों से रिपोर्टिंग एवं निगरानी की कार्यवाही संपादित की जा रही है। परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को परीक्षा समय का विशेष ध्यान रखे जाने की हिदायत दी गई है। नकल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की दृष्टि से परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रातः 8 बजे पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया है। यह निर्देश उनके प्रवेश पत्र पर भी अंकित है। केंद्र पर तलाशी, अनुक्रमांक अनुसार कक्ष आवंटन संबंधी कार्य इत्यादि के बाद 8:30 बजे परीक्षार्थी को कक्ष में प्रवेश दिया जाना होता है। अभिभावकों एवं परीक्षार्थियों से निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने की अपेक्षा की गई है।

किसानों को 40 प्रतिशत विशेष छूट देकर बैतूल का टर्बो टायर ग्लोबल इंवेस्टर समिट भोपाल में छाया

बैतूल। विगत दिनों ग्लोबल समिट का आयोजन भोपाल में किया गया। इसमें प्रदेश के कई नामीग्रामी उद्योगपतियों ने अपने स्टॉल लगाये थे। जिनमें बैतूल के टर्बो टायर एण्ड ट्यूब इंडस्ट्रीज का स्टॉल लोगों के बीच खासा चर्चा में बना हुआ था। दरअसल टर्बो टायर के द्वारा किसानों को टायर-ट्यूब खरीदने पर विशेष छूट दी जा रही है। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले संभाग मुख्यालय नर्मदापुरम पर इंवेस्टर समिट का आयोजन किया था, वहां भी बैतूल का टर्बो टायर छाया रहा था। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बैतूल के जनप्रतिनिधिगण भी पहुंचे थे, जिनमें केंद्रीय राज्यमंत्री डीडी उइके, विधायक हेमंत खण्डेलवाल, विधायक चंद्रशेखर देशमुख, विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, घोड़ाडोंगरी विधायक

गंगाबाई उइके ने टर्बो टायर एण्ड ट्यूब के स्टाल का अवलोकन किया। इनके उत्पादन को लेकर भी चर्चा की गई। इंडस्ट्रीज के मालिक अंबेश बलवापुरी, डायरेक्टर पर्व बलवापुरी, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष आशीष पांडे, सचिव पीयूष तिवारी ने भी जनप्रतिनिधियों को इस इंवेस्टर समिट के बारे में जानकारी दी। श्री बलवापुरी ने बताया कि ग्लोबल इंवेस्टर समिट का सफल आयोजन किया गया। इसमें लगभग 25 हजार करोड़ का निवेश हुआ है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी स्टील इंडस्ट्रीज के मालिक लक्ष्मी मित्तल, देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह अडानी के गौतम अडानी मौजूद थे। श्री बलवापुरी ने बताया कि इस निवेश से छोटे उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा। बैतूल के उद्योगपतियों ने इस ग्लोबल इंवेस्टर समिट में भाग लेकर वहां उपस्थित बड़े उद्योगपतियों एवं जनप्रतिनिधियों से बैतूल जिले में उद्योग को बढ़ावा देने पर चर्चा की है।

मप्र विद्युत मंडी पेशनर एसोसिएशन का सम्मेलन आज

बैतूल। मप्र विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन बैतूल का स्नेह सम्मेलन तथा प्रांतीय अधिवेशन 28 फरवरी शुक्रवार को तरंग वाटिका लिंक रोड में आयोजित किया जायेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रा. अध्यक्ष म.प्र.वि.म. पेंशनर एसोसिएसन जबलपुर सुरेश जायसवाल करेगे, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में हेमंत खंडेलवाल विधायक बैतूल, डॉ. योगेश पंडाग्रे विधायक आमला एवं विशेष आमंत्रित अतिथि व्ही. के. कैथवार (मुख्य अभियंता) (उत्पादन) मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारणी, अनूप सक्सेना (महाप्रबंधक) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. बैतूल (म.प्र.), एल. पी. अग्रवाल, प्रांतीय महासचिव म.प्र.वि.मं. पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर, आरसी सोमानी अध्यक्ष, विद्युत मण्डल पेंशनर्स एसोसिएशन इन्दौर, रामचरण साहू, अध्यक्ष प्रोग्रसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मप्र शाखा बैतूल मौजूद रहेगे। संगठन के पदाधिकारियों ने समस्त संगठन सदस्यों से कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह किया है।

एक महीने की बेटी की हत्यारी मां को उम्रकैद

104 पेज के फैसले में कोर्ट ने कहा, पुत्रियां सभ्यता, संस्कृति व राष्ट्र निर्माण का सशक्त हस्ताक्षर

भोपाल (नप्र)। ''जब एक पुत्री का जन्म होता है तो यह इस बात का निश्चायक सबूत है, कि ईश्वर मानव जाति से अप्रसन्न नहीं है, क्योंकि ईश्वर पुत्रियों के माध्यम से स्वयं को साकार रूप देता है।''

कवि रविन्द्र नाथ टैगोर इन पंक्तियों को अपने फैसले में शामिल करते हुए भोपाल के 23वें अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने गुरुवार शाम मासूम बेटी की हत्यारी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 104 पेज के निर्णय में विशेष टिप्पणी दी है।

जिसमें कहा गया कि वर्तमान में पुत्रियां सभ्यता, संस्कृति व राष्ट्र निर्माण का सशक्त हस्ताक्षर हैं। शास्त्रों में पुत्रियों को हृदयों का बंधन, भावों का स्पंदन, सृजन का आधार, भक्ति का आकार और संस्कृति का संस्कार माना गया है। वर्तमान में भारत जैसे विकसित राष्ट्र में पुत्रियों को साहस, सृजन, सेवा, सभ्यता, सौंदर्य एवं शक्ति के पुंज के रूप मे देखा जा रहा है।

बता दें कि भोपाल के खजूरी इलाके में मां ने ही पानी की टंकी में डुबोकर एक महीने की मासूम बेटी की हत्या कर दी थी। घटना 16 सितंबर 2020 की है। आरोपी मां फिलहाल जेल में बंद है। केस में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया ने पैरवी की थी।

मां को थी बेटे की आस, बेटी हुई तो नफरत हो गई- एक माह की किंजल मेवाड़ा ग्राम डहरिया थाना खजूरी निवासी सचिन मेवाड़ा की बेटी थी। सचिन गांव में खेती करता है और उसकी शादी करीब 14 माह पूर्व हुई। बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे सचिन की एक माह की मासूम अचानक लापता हो गई। पत्नी से पूछने पर उसने कहा की बच्ची को प्रेत आत्माएं ले गई हैं। परिजनों ने तलाश शुरू की तो करीब चार बजे उसकी बॉडी प्लास्टिक के एक पानी के ड्रम में मिली।

हवन के धुएं से भड़की मधुमक्खियां, बुजुर्ग की मौत

शहडोल में हमले में 13 लोग घायल; महाकुंभ से लौटा परिवार कर रहा था पूजा

शहडोल (नप्र)। शहडोल में मधुमक्खियों के हमले में एक बुजुर्ग की जान चली गई। हमले में 13 लोग घायल हो गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ से लौटा परिवार घर में हवन कर रहा था। इससे निकले धुएं से मधुमक्खियां भड़क गईं थी।

घटना ब्यौहारी स्थित गुरा गांव में गुरुवार दोपहर की है। रामकिशोर साहू के घर पर हवन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में करीब 50 लोग मौजूद थे। पास ही में पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था।

भागने समय गिरे बुजुर्ग, मधुमक्खियों ने काटा- मधुमक्खियों के हमले में प्रेमलाल कोल (60) की मौत हो गई। वे मधुमक्खियों से बचने के प्रयास में भागते समय खेत में गिर गए। उनका पैर लकड़ी में फंस गया और मधुमक्खियों ने उन्हें घेर लिया। उनका शव हवन स्थल से 200 मीटर दूर एक खेत में चार घंटे बाद बरामद हुआ।

तीन दिवसीय चलेगा मेला

शिवरात्रि पर प्राचीन पाषाण शिव पार्वती मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों की लगातार उपस्थिति

हीरालाल गोलानी सोहागपुर

नर्मदापुरम पिपरिया राज्य मार्ग पर सोहागपुर के प्रवेश द्वार पर स्थित शिव पार्वती मंदिर में आज से तीन दिवसीय मेला प्रारंभ हो गया है। सुबह 4बजे से ही प्राचीन पाषाण शिव पार्वती मंदिर में स्थापित प्रतिमा एवं ज्योतिलिंग पर जलाभिषेक श्रद्धालु भक्त जनों महिलाओं, युवतियों, बच्चों एवं नागरिकों ने किया। मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति निरंतर बनी रही। उल्लेखनीय है कि उक्त पाषाण प्रतिमा 16 सदीं की बताई जाती है। उक्त पाषाण प्रतिमा की स्थापना के अवसर मंदिर परिसर में एक माह का मेला आयोजित किया गया था। जिसमें बाजार की समस्त दुकानदारों ने यहीं अपना व्यवसाय एक महीने तक किया था। नगर के नामचीन प्रतिष्ठित समाजसेवियों एवं अलग-अलग विचार धारा वाले राजनैतिक हस्तियों ने बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा में निभाई थी। लेकिन वर्तमान में बाहरी दखल के कारण नगर की सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक ताना-बाना विक्रतिक हो गया है। यह नगर के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। यहां हमेशा कालांतर से सौहार्दपूर्ण वातावरण में नागरिकों ने अपना जीवनयापन किया है। जिसमें भले ही राजनीतिक विचारधारा अलग-अलग हो लेकिन सामंजस्य हमेशा बना रहता था। जिसकी आज पढ़े न लिखें नगर से विख्यात सोहागपुर के नागरिकों की महती आवश्यकता है। इसी शिव मंदिर के समीप ही हनुमान मंदिर स्थापित है। वहीं मंदिरों के सामने श्रीराम मंदिर एवं माता सरस्वती, माता लक्ष्मी एवं माता दुर्गा का मंदिर है। राज्य मार्ग के दोनों तरफ होने के कारण राजस्व प्रशासन, नगर पंचायत परिषद के कारण विशेष व्यवस्था की जाती है। वहीं राज्य मार्ग होने से अत्यधिक यातायात होने के कारण पुलिस भी माकूल इंतजाम करती है। सुबह से ही नगर निरीक्षक कंचन सिंह माकूल व्यवस्था में निर्देश देती रही। मंदिर पुजारी शुभम शर्मा ने बताया कि उक्त पाषाण शिव पार्वती मंदिर की प्रतिमा खेत में हल चलाते हुए निकली थी। जिसमें शिव पार्वती के अलावा सभी देवी देवताओं का समावेश एक ही पत्थर पर तराशा हुआ है। जिसमें ओम कार आरती स्वरूप प्रतिमा बनी हुई है।जो अपने आप में दुर्लभ है। इस प्रतिमा पर जलाभिषेक करने सोहागपुर ही नहीं आस-पास के सैकड़ों ग्रामों के ग्रामीण तीन दिन तक आकर पूजा-अर्चना करते हैं। वहीं पचमढ़ी महादेव को जाने वाले श्रद्धालु भी यहां दर्शन करना नहीं भूलते। इस मंदिर परिसर में बर्तनों,मनोहारी, खिलौने, खान-पान की दूकानों के अलावा नागरिकों के मनोरंजन के लिए अन्य नगरों के व्यापारी झूले भी लगाते हैं। जो बच्चों के आर्कषण का केंद्र होते हैं। बुधवार को मंदिर परिसर में मेले का शुभारंभ नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष श्रीमति लता यशवंत पटेल ने किया। इस अवसर पर नगरपालिका अधिकारी राकेश मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इधर मेले में सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

जनजातियों का चल रहा स्वर्णिम युग: राज्यपाल

जनजातीय परिवार अपने बच्चों की शिक्षा पर दें विशेष ध्यान, राज्यपाल ने पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों से किया संवाद

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि आज का युग जनजातियों के उत्थान के लिए स्वर्णिम युग है। जनजातियों के लिए केंद्र एवं राज्य शासन के द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा जनजातियों को सीधे तौर पर इनका लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे जनजातीय समुदाय सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में चिन्हित हैं। इनके उत्थान एवं समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे है। राज्यपाल श्री पटेल उमरिया जिले के ग्राम पंचायत लोढ़ा में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत लाभान्वित बैगा समुदाय के हितग्राहियों से संवाद कर रहे थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने जनजातियों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि जीवन में प्रगति के लिये शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति या समाज प्रगति नहीं कर सकता। जनजातीय समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण हैं, बेटे के साथ-साथ बेटी को भी शिक्षित करें, तभी हम प्रगति की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। उन्होंने जनजातीय छात्र-छात्राओं से कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों कि जनजातीय विद्यार्थियों में से कौन-कौन स्कूल जा रहा है अथवा नहीं यह देखें तथा बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को विद्यालय में कैसी शिक्षा दी जा रही है इसकी भी जानकारी लें तथा बच्चों के अभिभावक स्वयं बच्चों को एक घंटा समय निकालकर अवश्य पढ़ाएं। जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके तथा बच्चों का बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जनजातीय वर्ग के

विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश के जनजातीय महानायक टंट्या भील, रानी दुर्गावती सहित अन्य महानायकों की जीवनी को पढ़ाएं और बताएं कि उन्होंने देश के उत्थान में किस प्रकार योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सहरिया, भारिया एवं बैगा समुदाय के विकास के लिये केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पीएम जनमन योजना के लिये 24 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। पीएम-जनमन योजना से सहरिया, भारिया एवं बैगा समुदाय के लोगों को आवास के साथ-साथ अन्य मूलभूत सुविधायें भी मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से कहा कि जनजातीय लोग बहुत ही सीधे और सरल होते हैं, आप उनके यहां जाएंगे तो वह बिना खाना खिलाए आपको आने नहीं देंगे। वह अपनी थाली आपको परोस देंगे। आप जब भी अपने क्षेत्र के भ्रमण में निकलें तो जनजातीय परिवारों से अवश्य मिलें तथा उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है, अथवा नहीं इसकी जानकारी अवश्य लेकर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाएं।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि उमरिया जिला भी जनजातीय बाहुल्य जिला है, जहां जनजातीय परिवारों के लिए प्रशासन की ओर से अनेक कार्य किए गए हैं। इन परिवारों को आधार-कार्ड, आयुष्मान-कार्ड, लाड़ली बहना, लाड़ली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाओं का लाभ दिया गया है। पीएम जनमन योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को पक्के आवास की भी सुविधा मुहैया कराई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आवास प्रदान किए गए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिये आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय भी ग्राम पंचायत में संचालित है। राज्यपाल श्री पटेल ने लाड़ली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान कार्ड के हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र का वितरण किया।

राज्यपाल ने प्राथमिक शाला भवन टंगराटोला के तीसरी कक्षा के बच्चों से किया संवाद- राज्यपाल श्री पटेल ने उमरिया जिले के ग्राम पंचायत लोढ़ा के प्राथमिक शाला भवन टंगराटोला के कक्षा तृतीय के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व को बताया तथा उन्हें व्यायाम करने, मोटा अनाज/मिलेट्स का सेवन करने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने एवं भरपूर नींद लेने की बात कही। इस दौरान राज्यपाल ने बच्चों से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल अर्थात स्वयं के नाम भी पूछा। राज्यपाल द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बच्चों से सटीक जवाब सुनकर राज्यपाल ने खुशी जाहिर की।

राज्यपाल ने आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र टगराटोला में मनाया बच्चों का जन्म-दिवस- मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री पटेल ने उमरिया जिले के ग्राम पंचायत लोढ़ा के आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र टगराटोला में बच्चों का जन्मदिन केक काटकर मनाया तथा बच्चों को शुभाशीष एवं उपहार दिए। राज्यपाल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती कुसुम यादव से बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में मिलने वाली सुविधाओं एवं संदर्भ सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पौष्टिक आहार किट्स प्रदान की।

कार्यक्रम में सांसद शहडोल श्रीमती हिमाद्री सिंह, विधायक सुश्री मीना सिंह, विधायक बांधवगढ़ श्री शिव नारायण सिंह, कमिश्नर शहडोल श्रीमती सुरभि गुप्ता, पुलिस महा निरीक्षक शहडोल श्री अनुराग शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिले के समस्त विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे।

पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

मुख्यमंत्री शामिल होंगे

भोपाल। म.प्र.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र. शासन) द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को पूरे प्रदेश में 250 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आयोजन में प्रदेश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, वैज्ञानिक संस्थान एवं अन्य संस्थाएं भी सहभागिता करेंगी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इस वर्ष की थीम ''विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना'' है। इसके अन्तर्गत पूरे प्रदेश में विज्ञान दिवस समारोह, कार्यशालाएं, वैज्ञानिक-सत्र, संवाद, विज्ञान आधारित प्रतियोगिताएं एवं अनुसंधान टेक्नोलॉजी पर आधारित गतिविधियां संचालित होंगी।

मुख्य कार्यक्रम परिषद के नेहरू नगर स्थित सभागार में प्रातः 10.30 बजे प्रारंभ होगा जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। उनके द्वारा परिषद परिसर में ''सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्टेम एजुकेशन'' के उद्घाटन के साथ ही वे विद्यार्थियां के लिए आयोजित कार्यशालाओं अवलोकन एवं उनसे संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों से ऑनलाईन माध्यम से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर संबोधन किया जायेगा जिसमें बड़ी संख्या में वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी तथा नवाचार से संबंधित लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम में श्री संजय दुबे अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री अशोक कड़ेल संचालक हिन्दी ग्रंथ अकादमी, म.प्र. शासन भोपाल, श्री श्रीराम तिवारी, निदेशक विक्रमादित्य शोधपीठ संस्थान एवं संस्कृति सलाहकार, मुख्यमंत्री म.प्र.शासन, भोपाल तथा डॉ. अनिल कोठारी, महानिदेशक, म.प्र.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल भी उपस्थित रहेंगे।

प्रो. चित्र भूषण श्रीवास्तव विदग्ध को गार्गी गुप्त सम्मान

भोपाल। भारतीय अनुवाद परिषद दिल्ली , प्रति वर्ष अनुवाद कार्य हेतु गार्गी गुप्त सम्मान, प्रदान करती है। भारतीय विद्या भवन सभागार , नई दिल्ली में 28 फरवरी को भोपाल के प्रो चित्र भूषण श्रीवास्तव विदग्ध को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद के लिए इक्कीस हजार का सम्मान प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रो श्रीवास्तव ने संस्कृत के विश्व ग्रंथों भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूतम के समस्त श्लोकों का हिंदी छंद बद्ध गेय काव्य अनुवाद किया है। ये अनुवादित पुस्तके संस्कृत मूल , हिंदी काव्य , हिंदी अर्थ के साथ प्रकाशित हुई हैं। प्रो श्रीवास्तव ने बताया कि इससे संस्कृत नही जानने वाले भी इन अमर ग्रन्थ का काव्यगत आनंद उठा सकते हैं।

दस दिन बाकी, तेज हुई विधानसभा सत्र की तैयारी

विधायकों ने पूछे ऑनलाइन सवाल, मानसून सत्र से शुरू होगी ई-विधान सेवा

भोपाल (नप्र)। विधानसभा के 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच सत्र के पहले विधायकों ने विधानसभा सचिवालय के जरिए मोहन यादव सरकार से 1785 ऑनलाइन और 1154 ऑफ लाइन सवालों के के जवाब मांगे हैं। जिसमें 1448 तारांकित और 1491 अतारांकित सवाल शामिल हैं। इस तरह कुल 2939 सवाल हुए हैं।

विधानसभा की प्रक्रिया को हाईटेक बनाने की कार्यवाही के बीच बजट सत्र के पहले ऑनलाइन सवाल पूछे गए हैं। वहीं आफ लाइन सवाल करके भी विधायकों ने सरकार से जवाब चाहा है।

अब तक के सबसे छोटे बजट सत्रों में शामिल होने वाला मोहन सरकार का यह बजट सत्र सिर्फ नौ दिन चलेगा। इस सत्र के दौरान होली और रंगपंचमी जैसे त्योहार भी पड़ेंगे। ऐसे में सत्र के दौरान विधायकों की मौजूदगी भी कम रहने की संभावना जताई जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चलते 15 दिन आगे बढ़ाई गई बजट सत्र की तारीख को लेकर कांग्रेस पहले ही विरोध जता चुकी है।

विधवा महिलाओं को विवाह करने प्रोत्साहित करेंगे मंत्री

कैबिनेट फैसले के बाद आदेश जारी, शादी करने पर दो लाख रुपए मिलेंगे, प्रचार-प्रसार पर जोर

भोपाल (नप्र)। प्रदेश सरकार अब विधवा महिलाओं के विवाह को प्रोत्साहित करने जा रही है। इसके लिए मोहन कैबिनेट ने अपने सभी मंत्रियों से कहा है कि वे अपने विभाग, प्रभार के जिलों और क्षेत्र में विधवा महिलाओं को प्रोत्साहित करें। प्रदेश व जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार जाए, जिससे जरूरतमंद कल्याणियों (विधवा महिलाओं) को अधिक-से-अधिक लाभ मिल सके।

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट खत्म हो चुकी है। अब मंत्रियों को विभाग के बजट और समीक्षा के साथ जिलों में इस तरह के विवाह आयोजनों

पर भी फोकस करना होगा। सरकार ने ऐसी महिलाओं को कल्याणी नाम दिया है। इनके सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों के जरिए विवाह होने पर दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था भी तय कर रखी है।

24 जनवरी 2025 को मोहन कैबिने की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सामूहिक विवाह आयोजन के साथ ही कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिये मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिये कल्याणी विवाह पोर्टल tps://vivahportal.mp.gov.in भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद कल्याणियों की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो सके।

2018 में शुरू हुई योजना- प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और निशक्तजन सोनाली वायंगणकर ने दो दिन पहले जारी आदेश में मंत्रियों को विधवा विवाह के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी कैबिनेट के फैसले के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना वर्ष 2018 में प्रारंभ हुई है। योजना में कल्याणियों को विवाह के बाद राशि 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।

आज रिटायर हो जाएंगे अजीत केसरी, संजय शुक्ल बनेंगे एसीएस

जून, अगस्त, सितम्बर में रश्मि, मनीष और दीपाली को मिलेगा एसीएस बनने का मौका

भोपाल (नप्र)। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी शुक्रवार को रिटायर हो जाएंगे। केसरी के रिटायरमेंट के बाद एक मार्च से प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग संजय कुमार शुक्ल अपर मुख्य सचिव पद पर प्रमोट हो जाएंगे। इसके आदेश सामान्य प्रशासन विभाग कल जारी करेगा। इसके पहले जनवरी में अपर मुख्य सचिव गृह रहे एसएन मिश्रा और अपर सचिव अक्षय कुमार सिंह रिटायर हो चुके हैं।

वर्ष 2025 में अपर मुख्य सचिव स्तर के छह आईएएस अधिकारी रिटायर होने वाले हैं। इनके रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठता क्रम में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे और एमपी में पदस्थ आईएएस अफसरों को एसीएस पद पर प्रमोट किया जा रहा है। जनवरी में एसीएस एसएन मिश्रा के रिटायर होने के बाद राजस्व मंडल के अध्यक्ष बनाए गए अनिरुद्ध मुखर्जी को अपर मुख्य सचिव पद पर प्रमोट किया गया है।

इसके बाद 28 फरवरी शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण अजीत केसरी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इनकी जगह लेने वालों में एमपी में पदस्थ अफसरों में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ल का नाम सबसे ऊपर है। इसलिए कल ही शुक्ल को एसीएस बनाए जाने के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग जारी कर सकता है। दिल्ली में वित्त मंत्रालय में पदस्थ एमपी कैडर के एसीएस स्तर के अधिकारी मनोज गोविल का रिटायरमेंट मार्च में है। वे केंद्र में पदस्थ हैं, इसलिए उनके रिटायरमेंट पर किसी अधिकारी को प्रमोशन नहीं मिलेगा।

रश्मि शमी एक जून से बनेंगी एसीएस- जनवरी और फरवरी में दो आईएएस अफसरों के रिटायर होने के बाद अब मई में एसीएस विनोद कुमार रिटायर होंगे। विनोद कुमार के रिटायर होने के बाद रश्मि अरुण शमी एसीएस पद पर प्रमोट होंगी। इसके बाद जुलाई में मो. सुलेमान और अगस्त में मुख्य सचिव अनुराग जैन व एसीएस जेएन कंसोटिया का रिटायरमेंट है। जैन को एक्सटेंशन नहीं मिला तो एक सितम्बर से दो प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों को एसीएस बनने का मौका मिलेगा। सुलेमान के रिटायरमेंट के बाद प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी को एसीएस पद पर प्रमोशन मिलेगा। फिर दीपाली रस्तोगी और शिवशेखर शुक्ला का नम्बर आएगा।

पीएम जनजातीय समुदाय के लिए संवेदनशील

राज्यपाल ने कटनी के ग्राम कोठी में बैगा परिवारों से किया संवाद

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्राथमिकता के साथ लाभान्वित कर रही हैं। पीएम जन-मन योजना के द्वारा बैगा, सहरिया एवं भारिया विशेष पिछड़ी जनजातीय बसाहटों में पक्का आवास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल श्री पटेल ने यह बात कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील के पीएम जनमन ग्राम कोठी में बैगा जनजाति के लोगों से संवाद के दौरान कही।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के रूप में जनमन ग्रामों के समग्र विकास के लिए दूरदर्शी और संवदेनशील नेतृत्व मिलना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जनजातीय समुदाय के प्रति विशेष संवेदनशील हैं। समाज के पिछड़े वर्ग और व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सतत् काम कर रहे हैं।

पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश- राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल जनमन ग्राम कोठी में बैगा हितग्राहियों के साथ संवाद कार्यक्रम के पहले, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राहियों के घर भी पहुचें। उन्होंने योजना से लाभ मिलने के बाद हितग्राही के जीवन में आए बदलाव को जाना।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने सर्वप्रथम पीएम जनमन आवास हितग्राही चंदाबाई बैगा, भल्लू बैगा और सोनी बैगा को प्रधानमंत्री आवास योजना से बने पक्के आवास में विधि-विधान और पूजा-अनुष्ठान के साथ गृह प्रवेश कराया। राज्यपाल श्री पटेल का बैगा समुदाय के लोगों ने तिलक लगाकर और शाल पहनाकर स्वागत किया। बैगा परिवारों ने उपहार स्वरूप उन्हें लोक कला पर आधारित पेन्टिंग भेंट की गई।

स्वच्छता पर बनाएं रील, पाएं 2 लाख तक का इनाम

स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता, मंत्री बोले- रील बनाएं और स्वच्छता का संदेश फैलाएं

भोपाल (नप्र)। रील प्रतियोगिता के तहत राज्य सरकार युवाओं को दो लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। इसके लिए प्रतिभागियों को 15 अप्रैल तक गांवों में कचरे से जुड़ी जागरूकता पर रील बनाकर सरकार द्वारा निर्धारित लिंक पर अपलोड करनी होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए कहा कि, प्रदेशभर से प्राप्त रीलों में से सर्वश्रेष्ठ पांच प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि, गांवों में कचरा न फैले, इसके लिए कचरा प्रबंधन पर सभी को मिलकर काम करना होगा। इस उद्देश्य से 'स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता' शुरू की जा रही है। प्रतियोगिता के तहत नौजवान बेटे-बेटियां

और अभिभावक स्वच्छता व अच्छी आदतों पर रील बनाकर भेज सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल प्रतिभागी आर्थिक पुरस्कार प्राप्त करेंगे, बल्कि समाज को जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि, एक बार कैमरा उठाएं और स्वच्छता के संदेश के साथ रील बनाने के लिए आगे आएं।

मंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना की थी। इसी को साकार करने के लिए सरकार ने 'कचरा नहीं, यह कंचन है' का संदेश दिया है। यदि कचरे को सही तरीके से अलग किया जाए, तो यह आय का भी स्रोत बन सकता है।

मंत्री सारंग ने की जीआईएस में सहकारिता की फॉलोअप समीक्षा

सीपीपीपी के जरिये निवेश करने वालों के लिये निवेश विंग में नोडल अधिकारी करें नियुक्त

भोपाल (नप्र)। सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सहकारिता विभाग में निवेश विंग की स्थापना के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने विंध्याचल भवन स्थित सहकारिता विभाग में सहकारिता संबंधी निवेशकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा। साथ ही उन्होंने एक कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिये, जो आये प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद हायर लेवल पर प्रस्तुत करेगी। मंत्री श्री सारंग मंत्रालय में जीआईएस के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे।

हितग्राहियों को परस्पर लाभ देने के लिये सीपीपीपी मॉडल- मंत्री श्री सारंग ने कहा कि विभाग के को-ऑपरेटिव पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के हितग्राहियों को परस्पर लाभ प्रदान करने के साथ ही प्रदेश के दूसरे और तीसरे दर्जे के क्षेत्रों के विकास को तिगुनी गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इसीलिये निवेशकों का विशेष ख्याल रखा जाये। सिंगल विण्डो सिस्टम से किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण हो।

धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा 'श्रृंगेश्वर धाम': मंत्री सुश्री भूरिया

6.3 करोड़ रूपए से 250-300 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े घाट का किया जाएगा निर्माण

भोपाल (नप्र)। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के मार्ग दर्शन में जल संसाधन विभाग द्वारा के द्वारा माही एवं मधुकन्या नदी के संगम पर अवस्थित प्राचीन श्रृंगेश्वर धाम को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से लगभग 6.3 करोड़ रुपये का प्रस्ताव श्रृंगेश्वर घाट निर्माण सौंदर्यीकरण के लिए भेजा गया है। प्रस्ताव में जल संसाधन विभाग के माध्यम से नवीन मंदिर और प्राचीन मंदिर के मध्य लगभग 250-300 मी. लम्बा और 25 मी. चौड़ा घाट का निर्माण कर, श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था, गार्डन के साथ सुरक्षा रैलिंग बनाये जाने का प्रावधान है।

श्रृंगेश्वर धाम में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। धार्मिक पर्यटन की संभावना को देखते हुए मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने इस स्थल को संवारने के लिए ज़िला प्रशासन के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए थे ।किनारे पर घाट को इस तरह से बनाया जाएगा कि माही के बैक वाटर में भी यह पूरी तरह से सुरक्षित रहे। यह किनारे की मिट्टी के कटाव को भी रोकेगा। वर्तमान में घाट की स्वीकृति जल संसाधन विभाग से अपेक्षित है।

सुश्री भूरिया ने बताया कि पेटलावद क्षेत्र के झकनावदा से करीब 5 किमी दूर स्थित श्रृंगेश्वर धाम जन-जन की आस्था का केंद्र है। यह तीर्थ स्थल माही व मधुकन्या नदी के संगम पर स्थित है और इससे पौराणिक मान्यता जुड़ी है। बताया जाता है कि महान संत शृंगी ऋषि के सिर पर सींग था। अनेक स्थानों पर विचरण करते हुए जब वे माही नदी के तट पर पहुंचे तो वहां स्नान करने के बाद श्रृंगी ऋषि के सिर के सींग गल गए थे। तभी से इस स्थान का नाम श्रृंगेश्वर धाम हो गया। यह भी कहा जाता है कि यहां पर माही नदी में स्नान करने से कई रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए भी विशेष अवसरों पर यहां राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश सहित मध्यप्रदेश के कई दूर दराज के इलाकों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। जन आस्था को देखते हुए ही मैंने इस स्थल को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा था। इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि तौर पर हमारे जिले में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

कलेक्टर सुश्री नेहा मीना ने बताया इस प्रकार के सौंदर्यीकरण के माध्यम से धार्मिक पर्यटन के साथ ईको टुरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। आगामी 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ के तहत श्रृंगेश्वर धाम को शिवलिंग के टूरिस्ट सर्किट में जोड़ने के प्रयास किये जाएंगे। प्रस्ताव व घाट का डिज़ाइन बनाने में यह कोशिश की गई कि नए मंदिर व पुराने मंदिर को आपस में जोड़ा जा सके। टूरिज्म सेक्टर से जगह की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है व रोज़गार सृजित होता है। इसी के साथ देवझिरी प्राचीन तीर्थ स्थल पर भी घाट निर्माण, सौंदर्यीकरण के कार्य विभिन्न विभागों के समन्वय के माध्यम से किये जाना प्रस्तावित है।

वर्षभर होते हैं आयोजन- श्रृंगेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव, सोमवती अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या, श्रावण मास सहित कई धार्मिक आयोजन होते हैं। वर्ष 2023 में श्रृंगेश्वर धाम पर रुद्र महायज्ञ का भव्य आयोजन भी किया गया था। ब्रह्मलीन महंत काशी गिरी महाराज ने इस धाम को पूरी मेहनत व लगन के साथ स्थापित किया था। माही डैम के बैक वाटर में प्राचीन मंदिर जलमग्न हो गया। इसके बाद नए मंदिर को घाटी पर बसाया गया। यहां शिवलिंग, पंचमुखी हनुमान जी और ऋषि श्रृंगी, काशीगिरी और माही माता की प्राण प्रतिष्ठा की गई है।

न्यायालय तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 5105/अ-6/2024-25

:: उद्घोषणा पत्र ::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री आशुतोष दुबे आ. श्री कमलेश कुमार दुबे (2) श्रीमती प्रीति दुबे पत्नी श्री आशुताष दुबे निवासी जी-14, गोयल आनंद अपार्टमेंट, गुलमोहर, भोपाल, म.प्र., म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. 3507 (2) दिनांक 31/12/12 ग्राम बावड़िया कलां प.ह.न. ..... स्थित भूमि खसरा नंबर 78/3/1/2, 78/2/2/1, 78/3 रकबा 98.50 वर्गमीटर भूखण्ड क्र. 9 भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है।

2. उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 13/03/2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उप. स्थित होकर पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 27/02/2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-कोलार, भोपाल

राइट क्लिक

तमिलनाडु : 'भाषा युद्ध' और परिसीमन की पिच पर चुनावी मोर्चाबंदी

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। सत्तारूढ़ डीएमके ने जहां भाषा युद्ध और परिसीमन में संभावित अन्याय को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार और भाजपा पर हमले शुरू कर दिए हैं तो वहीं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके को महाभ्रष्ट सरकार बताकर उसे हटाने की दुंदुभि बजा दी है। यह साफ है कि राज्य में अब तक राजनीतिक रूप से कमजोर और हिंदुत्ववादी माने जाने वाली भाजपा ने आगामी चुनाव पूरी ताकत से लड़ने का मन बना लिया है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने फिर द्रविड राजनीति की शरण ली है। उन्होंने यह धमकी देकर कि 'तमिलनाडु एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार' है, केन्द्र सरकार और भाजपा के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। स्टालिन ने चुनाव क्षेत्र परिसीमन में तमिलनाडु को होने वाले संभावित घाटे का मुद्दा उछालकर हिंदी विरोध और परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिणी राज्यों को एकजुट करने की सुनियोजित राजनीतिक कोशिशें शुरू कर दी हैं। हालांकि हिंदी विरोध पर उन्हें ज्यादा समर्थन शायद न मिले, लेकिन परिसीमन पर स्टालिन को दक्षिणी राज्यों का साथ मिल सकता है, क्योंकि इन राज्यों का तर्क है कि चूंकि उन्होंने अपने राज्यों में जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया, इसके बदले में उन्हें संसद में कुछ सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। यह दक्षिण भारत की संसद में घटती आवाज का और क्षेत्रीय असंतुलन का पर्याय होगा, जो भारत जैसे संघीय राज्य में स्वीकार्य नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो देश एक ओर अवांछित विभाजन की ओर धकेला जा सकता है। हालांकि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में अपनी सभाओं में परिसीमन में 'अन्याय' की आशंका को पूरी तरह खारिज किया है।

दरअसल तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव अगले साल अप्रैल में होने वाले हैं और सत्तारूढ़ द्रविड मुन्नेत्र कडघम ने सत्ता में वापसी के लिए अभी से राजनीतिक मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। जिसमें तमिल भावनाओं को खुलकर हवा देना शामिल है। पिछले विस चुनाव में उसने अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) को करारी मात दी थी, जिसका मुख्य कारण अम्मा जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएम का नेता विहीन होना और पार्टी की अंतर्कलह थी। एआईएडीएमके के अब दो धड़े हैं। कुल मिलाकर यानी राज्य में विपक्ष का स्पेस खाली है। भाजपा धीरे-धीरे इस स्पेस को भरने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसे अभी तक कोई बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत तेजी बढ़ा है। बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। जबकि डीएमके और एआईडीएमके द्रविड और तमिल अस्मिता की राजनीति करती रही हैं। हिंदी थोपने और उत्तर भारत को आर्य संस्कृति बताकर उसका विरोध द्रविड पार्टियों का प्रमुख औजार है। दोनों पार्टियों के बीच सत्ता की अदलाबदली करिश्माई नेता के हिसाब से होती रही है। वैचारिक रूप से दोनों एक ही हैं। इस दलदल में भाजपा और आरएसएस की हिंदुत्व केन्द्रित राष्ट्रवाद की राजनीति एक अलग तासीर और आग्रह लिए हुए है, जिसका स्वीकार तमिल मानस बहुत धीरे-धीरे कर रहा है। अगले विस चुनाव में भी भाजपा को कोई बड़ी सफलता मिलेगी, यह मान लेना जल्दबाजी होगी, लेकिन उसकी राजनीतिक जमीन मजबूत हो सकती है। संभव है कि भाजपा भविष्य में सत्ता की दावेदार भी हो जाए। यही डीएमके की चिंता का मुख्य कारण है। मसलन 2020 के विस चुनाव में भाजपा को तमिलनाडु में मात्र 2.62 प्रतिशत वोट और 4 सीटें मिली थीं। यह चुनाव भाजपा ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में लड़ा था। बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने भाजपा से रिश्ता तोड़कर दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। लोस चुनाव में एआईएडीएमके को भी कोई सीट नहीं मिली। सीट भाजपा को भी नहीं मिली, लेकिन उसका वोट बढ़कर 18.18 प्रतिशत हो गया। यद्यपि इस वोट प्रतिशत वृद्धि में उन छोटे का दलों का भी योगदान था, जिनसे गठबंधन कर भाजपा एनडीए के बैनर तले चुनाव में उतरी थी। जबकि इस लोस चुनाव में डीएमके गठबंधन को 46.97 फीसदी तथा मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके को 23.05 प्रतिशत वोट मिला। अपनी एकजुटता और द्रविड राजनीति के मुख्य पैरोकार के रूप में डीएमके ने राज्य में प्रतिद्वंद्वी एआईएडीएमके को काफी हद तक खत्म कर दिया है, लेकिन भाजपा को वैचारिक, जमीनी और संसाधन के स्तर पर कैसे रोका जाए, यह उसकी पहली चिंता है।

यही कारण है कि एम के स्टालिन ने नई शिक्षा नीति और परिसीमन को मुद्दा बनाते हुए पोजिशनिंग शुरू कर दी है। ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में चेतावनी के स्वर में कहा कि देश में शैक्षणिक समानता के लिए सभी राज्यों को अपने यहां नई शिक्षा नीति लागू करनी होगी। तभी उन्हें केन्द्र से आर्थिक सहायता मिलेगी। इस पर स्टालिन ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि वो राज्य के रोके गए 2152 करोड़ रू. जारी करे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु किसी हाल में अपनी द्विभाषा (तमिल और अंग्रेजी) में शिक्षा की नीति से नहीं डिगेगा। स्टालिन ने कहा कि हम भाषाई आधार पर 'ब्लैकमेल' करने का विरोध करेंगे।

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार, स्कूलों में छात्रों को तीन भाषाएं सीखनी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होंगी। इसका मतलब है कि राज्य की भाषा के अलावा, बच्चों को कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा सीखनी होगी- ज़रूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। हालांकि, तमिलनाडु को आशंका है कि यह केन्द्र द्वारा हिंदी को 'पिछले दरवाजे' से थोपते हुए राज्य की भाषाई स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश है।

दरअसल त्रिभाषा नीति उसी पुराने त्रिभाषा फार्मूले का नया रूप है, जिसमें सभी राज्यों से अपने यहां बच्चों को तीन भाषा पढ़ाने की अपेक्षा की गई है। इनमें एक हिंदी अथवा स्थानीय भाषा, दूसरी अंग्रेजी तथा तीसरी कोई आधुनिक भारतीय भाषा होगी। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी भाषा किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी। देश के ज्यादातर राज्यों ने या तो नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है या फिर उस पर अपनी सहमति दे दी है। केवल तमिलनाडु ऐसा राज्य है, जिसने 1968 की पहली शिक्षा नीति को भी ठीक से लागू नहीं किया था, क्योंकि उसमें तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने की बात थी। नई शिक्षा नीति में अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को अलग से सभी स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने की बात भी है। इस पर स्टालिन का आरोप है कि संस्कृत की आड़ में तमिल भाषा का महत्व कम किया जा रहा है, जबकि तमिल भी संस्कृत जितनी ही पुरानी और सभी द्रविड भाषाओं का मूल है। उधर स्टालिन की केन्द्र को इस 'धमकी' के बाद केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसका 'उचित जवाब' दिया जाएगा। अब सवाल यह कि क्या नई शिक्षा नीति को लेकर केन्द्र और राज्य में कोई समन्वय संभव है या फिर विस चुनाव तक तो दोनो में तलवारें खिंची रहेंगी। दरअसल भाजपा और संघ के हिंदुत्व से सीधे सनातन पर शिफ्ट होने के पीछे भी डीएमके ही कारण थी। तमिलनाडु सरकार में उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने साल भर पहले चेन्नई में एक प्रायोजित कार्यक्रम में हिंदू धर्म की मुख्य धारा सनातन को 'बीमारी' की संज्ञा दी थी। इसके बाद भाजपा और संघ के सनातन को अपने प्रचार का मुख्य हथियार बना लिया। इसका उसे चुनावों में फायदा भी मिला।

हिंदी को लेकर तमिलनाडु का विरोध 1937 से है। वह देश में अकेला ऐसा राज्य है, जहां स्कूलों में राजभाषा और अघोषित रूप से राष्ट्रभाषा का स्वरूप ले रही हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। इससे नुकसान उन बच्चों का होता है, तो तमिलनाडु के बाहर अन्य राज्यों में नौकरी धंधा करना चाहते हैं। नतीजा यह है कि विद्यार्थी निजी स्तर पर हिंदी सीख रहे हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी परीक्षा में तमिल विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है। इसका सीधा अर्थ यही है कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध मुख्यतः राजनीतिक है और द्रविड राजनीति की प्रासंगिकता को कायम रखने की एक प्रभावी आड़ है। जबकि बीती आधी सदी में काफी कुछ बदल चुका है।

स्टालिन का दूसरा मुद्दा ज्यादा गंभीर और विचारणीय है। इस साल देश में 16वीं जनगणना होना संभावित है। साथ ही अगले साल 2026 में संसदीय व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का देश की बढ़ती आबादी के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से परिसीमन होना है। 5 (केन्द्र शासित पुदुच्चेरी सहित 6) दक्षिणी राज्यों और खासकर तमिलनाडु की चिंता यह है कि चूंकि बीते डेढ़ दशक में इन राज्यों की आबादी उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों की तुलना में कम बढ़ी है, ऐसे में नए परिसीमन में लोकसभा में उनकी सीटें कम हो सकती है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण भारत की घटती हिस्सेदारी। दक्षिणी राज्यों का वाजिब तर्क है कि चूंकि उन्होंने अपने यहां जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर आर्थिक सामाजिक स्तर पर तेजी से विकास किया, इसकी 'सजा' उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में घटती हिस्सेदारी के रूप में क्यों? मिले। स्टालिन का कहना है यदि परिसीमन का मुख्य कारक आबादी ही रहा तो तमिलनाडु की लोकसभा में 8 सीटें घट जाएंगी, जो वर्तमान में 39 है। सीटें घटने की यह चिंता तमिलनाडु के साथ-साथ दक्षिण के अन्य राज्यों में भी है। इसीलिए आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है और स्थानीय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए दो बच्चों की सीमा को भी हटा दिया है। अब यह मोदी सरकार पर निर्भर है कि वह देश के संघीय ढांचे को कायम रखने के लिए क्या करती है।

॥ मंदिरम् ॥

46

श्री कांतेश्वर मंदिर, कर्नाटक

श्री कांतेश्वर मंदिर (जिसे नंजुंदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है) भारत के कर्नाटक राज्य के तीर्थस्थल नंजनागुडु में शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह कावेरी नदी की सहायक कपिला नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नंजनागुडु को 'दक्षिण प्रयाग' या 'दक्षिण का प्रयाग' भी कहा जाता है। कन्नड़ में नंजू का मतलब है 'ज़हर देना'। नंजुंदेश्वर नाम का मतलब है 'ज़हर पीने वाला भगवान' (हलाहल, एक ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति दूध के महासागर के महान मंथन की किंवदंती से हुई है); इस प्रकार, शहर का नाम 'नंजनागुडु' पड़ा जिसका अर्थ है 'भगवान नंजुंदेश्वर का निवास स्थान'। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और अपने उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। एक बार इस मंदिर का दर्शन जरूर करे।

भोपाल में बोले- शिवराज

करने पड़ते हैं वोट दिलाऊ फैसले

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बार-बार चुनावों के कारण कई फैसले प्रभावित होते हैं। गवर्नेंस प्रभावित होती है, विकास रुक जाता है पैसे की बर्बादी होती है। कई बार तो वोट दिलाऊ फैसले भी करने पड़ते हैं। शिवराज ने भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज में आयोजित 'एक देश-एक चुनाव' कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया।

इस दौरान उन्होंने कहा- अपने देश में और कुछ हो या न हो लेकिन सारे राजनीतिक दल पांचों साल, 12 महीने, हर हफ्ते, 24 घंटे एक ही तैयारी करते हैं, वो है अगला चुनाव। उसी तैयारी में लगे रहते हैं।

शिवराज ने कहा कि अब पिछले साल नवंबर-दिसंबर में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव की थकान उतरी नहीं थी कि 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव आ गया। विधानसभा चुनाव में 6 महीने तो कुछ हुआ ही नहीं था। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण विकास के काम ठप थे। वो चुनाव हुए और चार महीने बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ गए। चार-छह महीने नहीं गुजरे कि फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव आ गए और नेता फिर चुनाव में भिड़ गए।

एक भी चुनाव हारे तो मीडिया कहती है जमीन खिसक गई- शिवराज ने कहा, अभी एक चुनाव निपटा नहीं कि दिल्ली का दंगल शुरू हो गया। दिल्ली के चुनाव खत्म नहीं हुए कि हम लोगों ने बिहार के लिए कमर कस ली। चलो बिहार। और कोई काम हो न हो, चौबीसों घंटे चुनाव की तैयारी। ये हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में कितने बाधक हैं। एक तो सभी की एनर्जी लगती है, जिसमें प्रधानमंत्री भी चुनाव की तैयारी में लगते हैं।

पैसा बर्बाद होता है, सरकारें लंबी प्लानिंग नहीं करतीं- शिवराज ने कहा- अलग-अलग चुनाव क्यों होने चाहिए? हर चार-छह महीने में चुनाव हो रहे हैं। गवर्नेंस प्रभावित होता है। धन का अपव्यय होता है। असल में तो औपचारिक खर्चा दिखता है, पीछे से और कितना खर्चा होता है। चुनाव आयोग ने इस चुनाव में गाड़ियों से पैसे पकड़े थे। एक तरफ धन का अपव्यय होता है, दूसरी तरफ सरकारें लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पातीं।

चुनाव के डर से सरकार में कई फैसले नहीं हो पाते- शिवराज सिंह चौहान ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। लेकिन, कई बार चुनाव के डर में कई ऐसे फैसले नहीं हो पाते कि वोट बिगड़ गया और नुकसान हो गया, तो वोट बचाओ। ऐसे कई फैसले प्रभावित होते हैं, जो बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। प्रदेश का विकास कर सकते हैं। देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं।

अगर संविधान में संशोधन करके लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएं, तो साढ़े चार साल जनता और विकास के लिए ईमानदारी से मिलेंगे। अपने देश में भी लोकसभा के चुनाव के साथ ओडिशा और तीन विधानसभा चुनाव हुए।

मोदी जी लोकप्रिय इसलिए एक साथ चुनाव से डर

शिवराज ने कहा- मैं पूछता हूं कि एक साथ चुनाव से डरते क्यों हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। जनता बहुत समझदार है। वो लोकसभा में अलग वोट डालती है, विधानसभा में अलग। ओडिशा में दो बार लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव हुए। उसी जनता ने पिछले चुनाव में राज्य के लिए बीजेडी के नवीन पटनायक को चुना और देश के लिए मोदी जी को चुना। अब समय आ गया है कि देश ये तय करे कि फालतू का खर्चा, चुनाव आचार संहिता के साथ विकास ठप होना, देश की प्रगति और विकास रुकना अब नहीं चलेगा।

तीन महीने सब छोड़कर झारखंड में पड़ा रहा

शिवराज ने कहा, चुनाव में पीएम, सीएम सब लगे रहे। केन्द्रीय मंत्री मुझे बनाया गया और कहा गया झारखंड के चुनाव में जाओ। तीन महीने वहीं पड़ा रहा। कृषि की तरफ ध्यान ही नहीं रहा। फोकस चुनाव पर हो गया।

मार्च के पहले सप्ताह बारिश के आसार, फिर गर्मी

भोपाल, उज्जैन-जबलपुर की रातें अभी ठंडी, 2-3 डिग्री बढ़ेगा तापमान

भोपाल (नप्र)। मार्च के पहले सप्ताह में मध्यप्रदेश के पश्चिम-उत्तरी हिस्से में हल्की बारिश होने के आसार है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के एक्टिव होने से ऐसा हो सकता है। इससे पहले 3 दिन तक दिन-रात का पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ा रहेगा। जिससे गर्मी का अहसास होगा।

मौसम विभाग के अनुसार, 2 मार्च से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है।

भोपाल में बादल छाए- इधर, बुधवार को भोपाल में सुबह से बादल छाए रहे। वहीं, रीवा, सतना, पन्ना और मैहर जिलों में भी मौसम बदला रहा। बाकी शहरों में आसमान साफ रहा। जिससे दिन के पारे में बढ़ोतरी देखने को मिली।

पांच दिन तक रहा ठंड का असर- पिछले 5 दिन से प्रदेश में हल्की ठंड पड़ी। मंगलवार-बुधवार की रात की बात करें तो इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 6.8 डिग्री, शहडोल के कल्याणपुर में 8.7 डिग्री, शाजापुर के गिरवर में 9.6 डिग्री और मंडला में 10.2 डिग्री दर्ज किया गया।

बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 12.6 डिग्री, इंदौर में 17.6 डिग्री, ग्वालियर में 15.5 डिग्री, उज्जैन में 13.8 डिग्री और जबलपुर में पारा 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार रैकवार ने बताया-फरवरी में कई वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होते हैं। अबकी बार भी ऐसा ही रहा। अब पारे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

चलती कार का टायर फटा, खड़े ट्रक से टकराई, भाई-बहन की मौत

नरसिंहपुर (नप्र)। नरसिंहपुर में चलती कार नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार में सवार भाई-बहन की मौत हो गई। वहीं बच्चों के चाचा ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।

हादसा गुरुवार दोपहर 3.30 बजे सुआतला थाना क्षेत्र में बरमान चौकी के पास हुआ। कार का टायर फट गया था, जिससे वह बेकाबू हो गई। बरमान चौकी प्रभारी आशीष बोपचे ने कहा कि कार में सवार बम्हनी गांव के हिमांशी ठाकुर (16) और प्रशांत ठाकुर (18) जान चली गई है। ये दोनों आपस में सगे भाई-बहन थे। वहीं भीकम ठाकुर (24) की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हो गई। ये दोनों बच्चों के चाचा थे।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने सपत्नीक दंगवाड़ा में की बोरेश्वर महादेव की पूजा-अर्चना

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सपत्नीक चंबल नदी तट पर स्थित अति प्राचीन श्री बोरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना कर अभिषेक किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व मंगल की कामना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन की ग्राम पंचायत दंगवाड़ा स्थित 4000 हजार वर्ष से अधिक प्राचीन बोरेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की। पूजन एवं जलाभिषेक पंडित श्री जगदीश शर्मा, श्री नमन शर्मा ने विधि विधान से संपन्न कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मन्दिर परिसर मे उपस्थित जन समूह को संबोधित किया और जिला पंचायत सीईओ श्रीमति जयति सिंह को सभी मांगो को पूर्ण करने के लिये आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिया।

1500 चिकित्सा शिक्षकों को अब जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान

कैबिनेट के निर्णय का पालन करने में लगे 16 माह 23 दिन, सरकार ने एनपीए की त्रुटि भी दूर की

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज, डेंटल मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 1500 चिकित्सा शिक्षकों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ अब 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दो दिन पहले इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि कैबिनेट ने 4 अक्टूबर 2023 को मंजूरी दे दी थी। जिसका पालन करने में विभाग को 16 माह 23 दिन लग गए। अब भी कोई सुगबुगाहट नहीं थी, पर डॉक्टरों ने आंदोलन कर दिया।

आखिर आनन-फानन में विभाग को आदेश निकालना पड़ा। विभाग ने (अव्यवसायिक भत्ता) की त्रुटि भी दूर कर दी है। यानी चिकित्सा शिक्षकों के वेतन में अब बढ़ोत्तरी होगी। साल 2018 के बाद खुले कॉलेजों के शिक्षकों को गिनें तो प्रदेश में वर्तमान में 15000

चिकित्सक हैं। जनवरी 2016 से मार्च 2018 तक बढ़े हुए वेतन का एरियर 2 से 4 लाख रुपए होगा।

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान दिया गया है, पर चिकित्सा शिक्षकों को इस वेतनमान का लाभ 1 अप्रैल 2018 से दिया गया। इसे लेकर चिकित्सा शिक्षक नाराज थे और साल 2019 से आंदोलन कर रहे थे। शासकीय चिकित्सक महासंघ मप्र के पदाधिकारी इस अवधि में कई बार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री से मिले।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने 4 अक्टूबर 2023 को 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से देने की मंजूरी दे दी। जिसका पालन नहीं हुआ, तो महासंघ ने आंदोलन की घोषणा की। 11 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी महासंघ पदाधिकारियों की भेंट हुई। 20-21 फरवरी को आंदोलन के बाद विभाग के अधिकारियों ने मांगें पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया। बता दें कि चिकित्सा शिक्षकों को यूजीसी के समकक्ष पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाता है।

15 माह के बढ़े वेतन पर चुप्पी- विभाग ने 7वां पुनरीक्षित वेतनमान 1 जनवरी 2016 से तो लागू कर दिया, पर 15 माह (जनवरी 2016 से मार्च 2018) के बढ़े हुए वेतन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अब डॉक्टर पसोपेश में हैं कि इस अवधि का एरियर दिया जाएगा या नहीं।

एनपीए में यह बदलाव- एनपीए अव्यवसायिक भत्ता है, जो वेतन के साथ दिया जाता है। यानी एनपीए और पे-बैंड को मिलाकर ही वेतन बनता है।